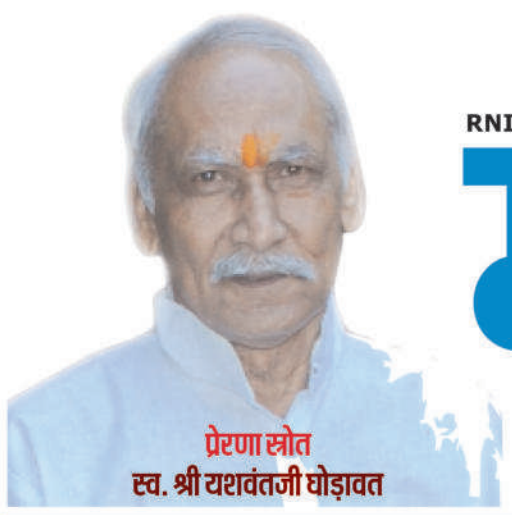
प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ..सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

आपको गतिविधि के समय स्थिर रहना और विश्राम के समय क्रियाशल रहना सीख लेना चाहिए।

इंदिरा गांधी

वर्ष-05, अंक - 14 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 05 जनवरी 2023 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

73 डॉक्टरों पर कार्यवाही सराहनीय पर कुकुरमुत्तों की तरह फैले फर्जी बंग्लादेशी व झोलाछाप डॉक्टरों का क्या...?

माही की गूंज, संजय भटेवरा

झाबुआ। हाल ही में एक खबर आई है कि, विदेश से पढ़ाई कर 73 डॉक्टर देश में जरूरी परीक्षा पास किए बिना अनुचित तरीके से इलाज कर रहे हैं... के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है साथ ही सीबीआई ने इन डाक्टरों से जुड़े 91 ठिकानों पर छापेमारी कर कुछ अहम दस्तावेज बरामद होने का दावा किया है।

निश्चित रूप से यह कार्यवाही काबिले तारीफ है, लेकिन क्या देश में केवल 73 डॉक्टर ही अवैध रूप से चिकित्सा का व्यापार कर रहे हैं..? भारत में मेडिकल की प्रैक्टिस यानी डॉक्टरी करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जिसमें 15 मार्च 2002 के बाद विदेश से मेडिकल पढ़ाई करने वाले सभी छात्रों के लिए एक परीक्षा पास करना अनिवार्य है इसके लिए नेशनल बोर्ड आफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) फारेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा (एफएमजीई) का आयोजन करता है। इसे पास करने वाले छात्र ही राज्यों की मेडिकल काउंसलिंग और मेडिकल काउंसलिंग ऑफ़ इंडिया में पंजीकरण करवाकर प्रेक्टिस शुरू कर सकते हैं। लेकिन आरोपित डॉक्टर बिना पंजीकरण करवाए ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रैक्टिस कर रहे थे। यही नहीं कुछ ने तो फर्जी दस्तावेज भी बनवा लिए थे, इसमें कई अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ सकती है। निश्चित रूप से आरोपियों को कड़ी सजा मिलना चाहिए। लेकिन 73 डॉक्टर ही क्यों...? देश के विभिन्न प्रदेशों में कोई भी अगर अवैध रूप से प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता है तो उसे भी समान सजा मिलना चाहिए।

लेकिन हकीकत ठीक इसके उलट ही है, माही की गूंज ने अपने पूर्व के अंकों में झाबुआ जिले में घुसपैठ करके आए कई बांग्लादेशी तथाकथित बंगाली डॉक्टरों का पर्दाफाश किया है। लेकिन कहा जाता है कि, इन तथाकथित बंगाली डॉक्टर जो कि, जिले के छोटे से छोटे गांव में कुकुरमुत्ते की तरह फैले है का नेटवर्क तथा संगठन मजबूत है और इसी नेटवर्क और संगठन के बलबूते आज तक कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। यही नहीं इन्होंने भी फर्जी रूप से जिले के मूलनिवासी जैसे ही अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी व अन्य दस्तावेज बना लिए हैं। यही नहीं कई गांवों में यह अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को मिलने वाला लाभ का भी उपयोग कर रहे हैं। कई ने गांवों में पक्के मकान बनवा लिए हैं... जॉब कार्ड बनवा लिए हैं उनके नाम पर फर्जी मजदूरी भी की जा रही है और उनके खाते में फर्जी मजदूरी की राशि भी जमा हो रही है।

इतना सब कुछ होने के बाद भी ये अपने मजबूत नेटवर्क और संगठन के बलबूते बेखौफ होकर प्रषासनिक साठ-गाठ से ही लगभग हर गांव में इलाज कर रहे है... इंजेक्शन लगा रहे है... बाटल लगा रहे हैं...। माही की गूंज की पड़ताल में यह तथ्य भी सामने आया है कि, इन तथाकथित बंगाली डॉक्टर पर कोई प्रशासनिक कार्यवाही ऊपरी दबाव से होती भी है तो इन्हें पूर्व में सूचना मिल जाती है। जिससे कार्यवाही के पूर्व ही ये लोग ताला लगा कर भाग जाते हैं और प्रशासन कागजी कार्यवाही के लिए अपनी औपचारिकता पूर्ण कर लेते हैं। अगर किसी का कोई केस बनता भी है तो इनका संगठन लेन-देन करके मामले को रफा-दफा करवा देता है और प्रशासन भी औपचारिकता निभाकर अपने कर्तव्यो की इतिश्री कर लेता है।

जिस प्रकार सीबीआई ने अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहे 73 डॉक्टरों के ठिकानों पर कार्यवाही की है, उसी प्रकार जिले सहित प्रदेशभर के गांवों और कस्बों में प्रशासन इस प्रकार कार्यवाही करें तो कई फर्जी डॉक्टरों के कई राज सामने आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए ईमानदारी और मजबूत इच्छशक्ति की आवश्यकता है।

एसपी अगम जैन ने नव वर्ष के साथ ही 14 अधिकारियों का किया हेर-फेर

माही की गूंज, झाबुआ। प्रशासनिक कसावट एवं पुलिसिया कार्रवाई एवं नियंत्रण के लिए एसपी के पास अधिकार होता है कि, वह समय-समय पर अपने अधीनस्थ अधिकारी व पुलिसकर्मी का स्थानांतरण कर पुलिस कार्रवाई को मजबूत करें।

इसी कड़ी में 2023 नव वर्ष में 3 जनवरी को एसपी अगम जैन ने 14 अधिकारी के स्थानांतरण की सूची जारी की जिसमें कल्याणपुरा थाना प्रभारी दिनेश रावत को काकनवानी थाना प्रभारी पदस्थ किया गया। थांदला थाना प्रभारी कौशल्या चौहान को कल्याणपुरा थाना प्रभारी, डीआरपी लाइन झाबुआ निरीक्षक कैलाश चौहान को थांदला थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी कुंदनपुर पल्लवी भाबर को चौकी प्रभारी पिटोल, चौकी प्रभारी पिटोल रमेश कोली को चौकी प्रभारी रंभापुर, चौकी प्रभारी मदरानी रुकमणी अहिरवार को चौकी प्रभारी कुंदनपुर, चौकी प्रभारी बामनिया पृथ्वीसिंह डामोर को चौकी प्रभारी मदरानी, चौकी प्रभारी रंभापुर नवलसिंह बघेल को चौकी प्रभारी खवासा, चौकी प्रभारी खवासा जगन्नाथ कनाश को थाना झाबुआ, थाना थांदला उप निरीक्षक अशोक बघेल को चौकी प्रभारी बामनिया, थाना काकनवानी उप निरीक्षक नरेंद्र राठौर को चौकी प्रभारी पारा, चौकी प्रभारी पारा हीरालाल मालीवाड़ को थाना थांदला, चौकी प्रभारी मोरडुडिया रज्जनसिंह गणावा को चौकी प्रभारी हरिनगर, राणापुर थाना सहायक उपनिरीक्षक लाखनसिंह भाटी को चौकी प्रभारी मोरडुडिया नियुक्त किया। उक्त स्थानतरण पर कई प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इन स्थानतरणों में कुछ प्रभारी जैसे खवासा, बामनिया की तरह जिनका ट्रांसफर तीन-चार माह पूर्व ही हुआ था और वह क्षेत्र को कुछ समझ पाते उसके पहले ही उन्हें रवानगी दे दी गई। तो वही थांदला कोशल्या चौहान को क्षेत्र में अपनी मनमानी के साथ कार्रवाई करने का तमका लगा है, जिसे उनकी इच्छा से कल्याणपुरा थाने में नियुक्त किया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। चुंकि कौशल्या चौहान पूर्व में कल्याणपुरा थाने की प्रभारी रह चुकी है और जिले में गुजरात के सीमावर्ती थानों की तर्ज पर ही यहां पुलिस की कमाई अच्छी खासी होती है जिसके लिए इच्छानुसार कल्याणपुरा भेजे जाने की बात चर्चा में है। इसी तरह कुछ ना कुछ अन्य चौकी एवं थाना प्रभारी के स्थानांतरण पर भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है।

अधिकारियों से उठता जनता का विश्वास, कलेक्टोरेट में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, मगर सावन के अंधे को सब हरा-भरा

माही की गूंज, झाबुआ।

''अजगर करे ना चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम'' यह लोकोक्ति बहुत ही प्रचलित कहावत है। इसका सीधा सा अर्थ यह कि, अजगर को किसी की नौकरी नहीं करनी होती और पक्षी को भी कोई काम नहीं करना होता, ईश्वर ही सबका पालनहार है, इसलिए कोई भी काम मत करो ईश्वर स्वयं देगा। आलसी लोगों के लिए मलूकदास का ये कथन बहुत ही उचित है। इसी कथन पर इन दिनों जिला प्रशासन पूरी तरह से खरा उतरता नजर आ रहा हैं। जिला प्रशासन की तानाशाही इन दिनों अपने चरम स्तर पर है। मजबूरों और फरियादियों की सुनवाई को नजर अंदाज करना आम बात हो चुकी है तो भ्रष्टों और आलसी अधिकारियों को प्रशासन का खुला संरक्षण प्राप्त हो रहा हैं। जिला मुख्यालय पर बैठे प्रशासन के आला अधिकारी शिकायत लेकर पहुंचने वालों को खरी खोटी सुनाते नजर आते है। वहीं भ्रष्ट और आलसी अधिकारी आरोपियों को खुला संरक्षण देने से बाज नहीं आते। अधिकारी जिले में पहली बार कलेक्टर बनकर आई रजनीसिंह को सावन के अंधे की तरह सबकुछ हरा-हरा ही दिखाते तो उन्हे भी सब कुछ हरा-भरा ही नजर आता। मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पिछले वर्ष दिसम्बर माह की आखरी जनसुनवाई में जयस के कुछ कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में बन रहे गुणवत्ताहीन डेम की शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर साहिबा ने अपना गुस्सा दिखाते हुए उलटा चोर कोतवाल को डांटे तर्ज पर फटकार लगाते हुए रवाना कर दिया। जिस डेम के निर्माण को लेकर यह पूरा घटना क्रम हुआ उसके बावजूद मेडम ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि, क्या वाकई निर्माणाधीन डेम में किसी तरह की कोई अनियमित्ता बरती जा रही है। फरियादियों को यह कहते हुए टरकाना कि, ''क्या तुम इंजिनियर हो, तुम्हे कितनी तकनीकि जानकारी है, आखिर हो क्या तुम, तुम लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हो और कार्य में बाधा डाल रहे हो''। कुल मिलाकर कलेक्टर मेडम का यह मानना है कि, डेम निर्माण में कोई अनियमित्ता नही बरती जा रही, सबकुछ गुणवत्ता पूर्ण हो रहा है। अपने अधिनस्तों के कहे अनुसार ही मेडम यह फैसला कर रही है। जबकि जमीनी स्तर पर हकीकत में जमीन-आसमान का फर्क साफ दिखाई पड़ता है। मीडिया में उजागर होते मामलों को सीधे तौर पर कलेक्टर रजनीसिंह द्वारा नकारा जा रहा है। एक कलेक्टर का यह व्यवहार मीडिया और फरियादियों के लिए ठीक तो नहीं कहा जा सकता।

थांदला ब्लॉक के ग्राम बालवासा में जल संसाधन विभाग द्वारा बनाए जा रहे 7 करोड़ से अधिक के बैराज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बैराज को लंबाई से छोटा बनाने का आरोप है। लंबे समय से चल रहे इस बैराज विवाद में भाजपा जिलाध्यक्ष ने बैराज पर पहुंच कर मौका मुआयना किया। नपती के दौरान निर्माणाधीन बैराज की लंबाई लगभग 10 मीटर कम पाई गई। बैराज जहां बनना था वह उस स्थान पर न बनकर 100 मीटर आगे बनाया जा रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य को रोकने का कहा लेकिन अधिकारियों ने कार्य को नही रोका। यह कोई पहला मौका नही है जब बैराज के संबंध में किसी ने आपत्ती जताई हो। इससे पहले भी कई बार कई संगठनों ने बैराज निर्माण पर आपत्ती ली है। मगर आंख से अंधे और कानों से बहरे प्रशासन को कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दिया। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन लगातार इस मामले की शिकायत कलेक्टर को करता रहा है लेकिन कलेक्टर है कि, अपने अधिनस्तों या विभाग पर कोई कार्रवाई करने के बजाय फरियादियों को ही अपने गुस्से का शिकार बना रही है। अब तो भाजपा जिलाध्यक्ष ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बैराज में हो रही अनियमित्ता को उजागर किया है। बैराज में अभी से दरारे होने का भी दावा किया जा रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष भानु भूरिया का कहना है कि, वे इस मामले में मुख्यमंत्री को शिकायत करेंगे। वैसे तो इस बैराज में और भी कई खामियां है, लेकिन जिला प्रशासन और कलेक्टर यह मानने को ही तैयार नही है कि, बैराज निर्माण में अनियमित्ता बरती जा रही है। जिला प्रशासन की विफलताओं का आलम यह है कि, इन दिनों धरनों और ज्ञापनों का दौर थमने का नाम नही ले रहा है। जिले में खाद्यान आपुर्ति को लेकर बरती जा रही लापरवाहियां भी जग जाहिर है, लेकिन इस मामले में भी कलेक्टर द्वारा किसी तरह की कोई गंभीर कार्रवाई अब तक दिखाई नही पड़ रही है। केवल अधिकारियों से मामले दिखवा भर लेने से तो बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि जिन अधिकारियों को कलेक्टर मामले सौंप रही है, असल में गड़बडियां भी उन्ही अधिकारियों की नाक के नीचे की जा रही है। इस स्थिति में यह तय है कि समस्या का समाधान होने की बजाय सिर्फ लीपापोती ही होना है। एक उदाहरण यह भी है कि, जिला मुख्यालय पर होने वाले प्रदर्शनों में प्रदर्शन कारी किसी भी अधिकारी पर विश्वास नहीं जता पा रहे है। पिछले दिनों में कलेक्टोरे में होने वाले प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारियों ने सीधे तौर पर अपनी शिकायत कलेक्टर को ही देने की जिद की है। मंगलवार को भी इसी तरह के नजारे देखने को मिले। अपनी मांगों को लेकर एनएसयुआई का प्रदर्शन हो या खनन माफियाओं से सताए जा रहे ग्रामीणों द्वारा किए गए प्रदर्शन, कोई भी एसडीएम, अपर कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन देने को तैयार नहीं। प्रदर्शन कारियों की सिर्फ एक ही मांग कलेक्टर को ही अपनी शिकायत सौपेंगे। इससे यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि, जिले की जनता का विश्वास प्रशासनिक अधिकारियों से किस तरह उठता जा रहा है। बावजूद इसके कलेक्टर अपने अधिनस्तों के दम पर ही जिले की कमान सम्भाले हुए है। अधिनस्त अधिकारी जो दिखाते वही कलेक्टर मेडम को सांवन के अंधे की तरह हरा-हरा ही नजर आता दिखाई पड़ रहा है। कलेक्टर की कार्यप्रणाली भी जिले की जनता को अब तक समझ नहीं आ रही है। आम जनता के लिए कलेक्टर की फटकार, उनका विश्वास कमजोर कर रही है और बात आंदोलन, धरना प्रदर्शन तक पहुंच रही है। कलेक्टोरेट के गलियारे जिला प्रशासन और कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी से गूंज रहे है। प्रशासनिक तानाशाही इतनी कि, कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए विधायक को घंटो इंतजार करना पड़ रहा है तो सत्ताधारी दल के जिलाध्यक्ष तक की सुनवाई कहीं होती नजर नहीं आ रही है। हालात को देखते हुए जिले की जनता इस कशमकस में है कि, करें तो करें क्या और जाएं तो जाएं कहां। जिले में अफसरशाही इतनी हावी के है कि, अधिकारी या तो काम नही करते और अगर करते है तो अकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाते है। स्थिति इतनी विकराल बनती जा रही है कि, यह कहावत स्वतः ही चरितार्थ होती नजर आ रही है। ''अजगर करे ना चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम''।

स्वच्छता के नाम से करोड़ों रुपये खर्च पर स्थिति बद से बदतर, सुचारू व्यवस्था नहीं कर पाते तो क्यों योजनाओं के नाम से कर रहे खाली सरकारी खजाना

सार्वजनिक शौचालय को चिचलाना में अपनी सम्पती मानकर कर लिया कब्जा।

खरखड़ी में बिना गाईडलाईन से गड्ढे में बनाया शौचालय गंदगी से पसरा पड़ा है।

माही की गूंज टीम के साथ जगराम विश्वकर्मा की रिपोर्ट

अलीराजपुर। विकास की मुख्य धुरी ग्राम पंचायत होती है और सरकारें भी मूलभूत सुविधाओं के साथ आम नागरिकों की सुविधाओं के लिए पंचायत स्तर से ही क्रियान्वयन हो सके की योजनाएं बनाती है। सरकार योजना तो बना देती है लेकिन उन योजनाओं का निर्वहन वास्तविक रूप से ग्राम स्तर पर हो रहा है कि, नहीं इसकी कोई मानिटरिंग नहीं की जाती है, नतीजन जो योजनाए सरकार ने लागू की है और उस योजना पर आम लोगों की मेहनत का पैसा सरकारी खजाने से निकालकर करोड़ों खर्च कर दिए पर वह योजना बदहाल हाल में ही रो रही है।

ऐसी ही केंद्र सरकार की एक योजना स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की परिकल्पना के साथ देश के प्रधानमंत्री की सोच पर संपूर्ण देश के साथ मध्यप्रदेश में सार्वजनिक सुलभ शौचालय को योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल तक धरातल पर लाने का प्रयास किया। ताकि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की परिकल्पना पूरी हो सके। परंतु यह एक अच्छी योजना भी करोड़ों खर्च करने के बाद भी व्यवस्थाओं के अभाव में आंसू बहा रही है।

अलीराजपुर जिले की ही बात करें तो, जिले की विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में सुलभ शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर आदि के नाम से लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए। यह शौचालय स्थल बनाए तो गए है, पर इसका लाभ आम लोगों को मिल सके ऐसी कोई सुचारू व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण केंद्र सरकार की यह योजना महज ही सरकारी नुमाइंदे खजाने से राशि निकालकर कार्य के नाम पर बंदर बांट करने के उद्देश्य से जिले में हर जगह खासकर वह पंचायत जो कि मुख्य सड़क मार्ग के पास है या उससे सटी हुई पंचायते है जहां सुलभ शौचालय अथवा स्वच्छता परिसर का निर्माण महिला व पुरुष के लिए अलग-अलग डिजाइन, लंबाई -चौड़ाई, बिजली फिटिंग व इन शौचालयो को सार्वजनिक उपयोग करने हेतु तथा व्यवस्थाओं के संचालन में नियमित खर्च राशि के लिए दुकानें बनाकर उसे किराए पर देने आदि अलग-अलग तरीके से लाखों रुपए खर्च कर निर्माण कराया गया। वही इन्हें आकर्षित रंगों से पोत कर गुणवत्ता में सेंध लगाकर राशि आहरण कर बंदर बांट कर ली। लेकिन इन शौचालयों पर व्यवस्थाओं के अभाव के चलते अनुपयोगी होकर बदहाली के हाल रो रहे हैं। न हीं यहां पानी की व्यवस्था है और न ही इसका संचालन किया जा रहा हैं। कई जगह इन शौचालयों पर ताले लगे हैं तो कई जगह जहां ताले खुले हैं वहां पूरी तरह से शौचालय गंदगी से सटे पड़े हैं, तो कईयों ने तो इनपर अपना निजी कब्जा कर अपना बसेरा बना लिया है।

केंद्र शासन की विशेष पहल पर राज्य शासन से जिले में जनपद पंचायतों द्वारा बनाए गए इन शौचालयो की हकीकत अलीराजपुर से दाहोद राष्ट्रीय मार्ग पर बने शौचालय की ही बात करें तो महिला-पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय व पेशाब घर बनाए गए साथ ही अगले हिस्से में दो दुकानें बनाई गई।

निर्माण के बाद दो पानी की टंकी तथा नीचे नल आदि के साथ ही विद्युत व्यवस्था हेतु बिजली फिटिंग भी करवाई गई इतनी सारी सुविधा देने के बाद भी व्यवस्थाओं के अभाव में यह बदहाली के हाल रो रहे हैं। यहां न तो पानी है और न ही यहां आस-पास कोई पानी भरने की व्यवस्था। बगैर कोई साधन व बगैर पानी के शौचालय का उपयोग कैसे...? यह विचारणीय प्रश्न है।

यहां लाइट फिटिंग तो कर रखी लेकिन यहां विद्युत कनेक्शन नहीं है जो दुकानें बनाई गई थी उनमें दुकानें कौन लगाएगा या दुकानें किराए से देना थी ताकि इनके किराए से आने वाले पैसों से इसका रख-रखाव किया जा सके। किराए के साथ कुछ लोगों को रोजगार मिलने की कल्पना की गई थी। अलीराजपुर से जोबट, आजादनगर से नानपुर आदि ग्रामों की सड़क किनारे ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित स्वच्छता परिसर बेकार पड़े हैं। आंबुआ में पंचायत भवन के सामने बना स्वच्छता परिसर में भी ऊपर पानी की टंकी रखी गई नल कनेक्शन बिजली की फिटिंग की गई है मगर पानी तथा लाइट का पता नहीं है। महिला शौचालय पर अभी भी ताला पड़ा है। मजबूरन महिलाओं को पुरुष मूत्रालय एवं शौचालय में जाना पड़ता है। हालांकि यहां दोनों दुकानें किराए पर दे दी गई है मगर वह गोदाम के उपयोग में आ रही है। साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं होने से गंदगी भरी पड़ी है।

ग्राम चिचलाना में तो जमीन मालिक ने कब्जा कर शौचालय को रैन बसेरा तथा निवास स्थल बनाकर दुकान चला रहा है। ग्राम वड़ी में यह भवन खड़खड़ी टेकरी पर बना है जिसमें ताले लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत खरखड़ी द्वारा बन्द घुसबयड़ा फाटे के पास सड़क से नीचे गड्ढे में शौचालय बनाया गया है, इसमें भी पानी के अभाव में गंदगी भरी पड़ी है। आशा है कि, एक अच्छी जनहितेषी योजना सुविधाओं के अभाव में बदहाल हो रही है और शासन का लाखों का खर्च बेकार जा रहा है कुछ समय बाद यहां खण्डहर न लगने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा आश्चर्य नहीं होगा।

अगर यह स्थिति जिले के मुख्य मार्ग पर ही दिख रही है तो तय है जिले में सुदूर ग्रामीण अंचल में इन शौचालयो की क्या स्थिति होगी यह सोचा जा सकता है। इसलिए शासन की योजनाओं का सही लाभ जिले की जनता को मिले और प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की परिकल्पना को पूरा करना है तो जिला प्रशासन अपनी आंखों से पट्टी हटाकर इस और अपना ध्यान आकर्षित कर सुचारू व्यवस्थाओं के साथ इन शौचालयों का संचालन हो पर अपना कार्य करें।

वड़ी में व्यवस्था के अभाव में ताले लगे पड़े है।

आम्बुआ में व्यवस्था के अभाव में बदहाल स्थिती में शौचालय।

माही परियोजना के अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही से किसानों को समय पर नहीं मिला पानी

लगातार मांग करने के बाद रात में पहुंचे माही के जिम्मेदार, आश्वासन लेकिन पानी नही

माही की गूंज, पेटलावद।

क्षेत्र के किसानो को उन्नत बनाने के लिए माही परियोजना के माध्यम से नहर पहुचाई गई। लेकिन माही परियोजना के अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत और लापरवाही की भेंट चढ़ी उक्त परियोजना के कारण सैकड़ो किसान नहर के दायरे में आने के बाद भी वंचित रह गए। ठेकेदार द्वारा नहर निर्माण के लिए तैयार कुँए और लाइन के अव्यवस्थित कार्य के कारण क्षेत्र के किसानों की फसल लगभग खराब होने की स्थिति में पहुँच गई है। माही परियोजना प्रोजेक्ट सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, सरकार ने यह राशि इसलिए खर्च की कि, किसानों को भरपूर पानी मिले, किसानों की फसल अच्छी हो उत्पादन अधिक हो ताकि किसानों की आय दोगुनी हो। परंतु अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत के कारण माही परियोजना का जो प्रोजेक्ट है, उसमें ग्राम खोरिया तहसील पेटलावद जिला झाबुआ माही परियोजना-6 का जो कुआं बना हुआ था, वह कुआं एक बार टेसिंटग पानी में ही गिर चुका था। फिर ठेकेदार के द्वारा पुनः बनाया गया जिससे कार्य की गुणवत्ता पता चलती है कि, किस गुणवत्ता में काम किया गया है। दूसरा जो कुए बने हुए हैं उस कुएं के ऊपर केविन सेट लगाना, सरकार के प्रारूप में है परंतु माही परियोजना-6 में खेत के पास में दो पानी टैंक हैं दोनों कुए पर कोई केबिन सेट लगा हुआ नहीं है। तीसरा कुए से किसानों के खेत तक जो पाइप डाले हैं वह ठेकेदार के द्वारा लापरवाही पूर्वक डाले हैं। मात्र जमीन से 1 या 2 फीट अंदर डालने से टोटल पाइप, हाल से हकाई-जुताई में किसानों के खेत में ही निकल चुके है। किसानों से फील्ड में जाकर पता किया तो पता चला माही परियोजना का जो पाइप करोड़ों रुपए लगाकर किसानों के खेत तक डाले हैं, उसमें एक भी बार पानी नही आया। क्योंकि ठेकेदार ने भ्रष्टाचार करने हेतु स्टिमेंट से विपरित जाकर पाईप लाईन ऊपरी सतह पर ही डाल दिये जिसकी वजह से हकाई-जुताई में टोटल पाइप निकल चुके हैं तथा टूट चुके हैं। यहा देखा जा सकता है कि किस तरह से सरकार का करोड़ों का प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढा दिया गया।

रात में क्षेत्र का दौरा करते अधिकारी।

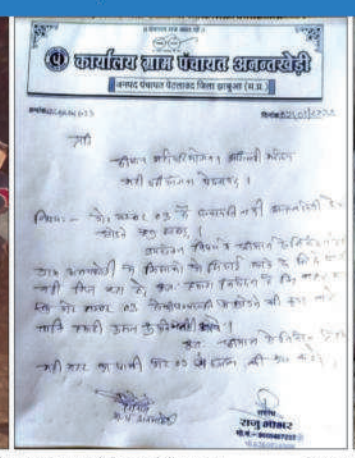

पानी नही मिलने पर ग्राम पंचायत ने विभाग को लिखा पत्र।

इस प्रकार अब तक सूखे पड़े हैं ठेकेदार द्वारा बनाये गए कुप।

ठेकेदार का गुणवत्ताविहीन कार्य

ठेकेदार ने किस निम्न स्तर या गुणवत्ता का कार्य किया है इसकी जानकारी मौका देख कर ही पता चलता है। किसानों को ठेकेदार की लापरवाही के कारण पानी नहीं मिला है इसकी जांच होनी चाहिए।

कृषक रामेश्वर राठौर ने बताया कि, ठेकेदार ओर विभाग की लापरवाही के कारण हमको पानी नही मिला इसलिए दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसानों का हक मारने का कोई ना सोचे। शिवराज मामा चाहते हैं कि, किसानों का भला हो पर कुछ लोग होते हैं की वह किसानों का भला नहीं अपना ही भला चाहते हैं। इस के चक्कर में किसान बेचारा परेशान होता रहता है। माही परियोजना के जिम्मेदार अधिकारी रात में मौका देखने पहुचे जरूर लेकिन किसानों के खेत तक पानी नही पहुँचा सके। बताया जा रहा है इस वर्ष ठेकेदार का टेंडर खत्म होने वाला है और भारी लापरवाही और घटिया निर्माण के बाद भी ठेकेदार का भुगतान कर दिया जाएगा। जबकि योजना और सरकार की मंशा ठेकेदार ने कोई कार्य नही किया है।

सीएम हेल्पलाइन पर गलत जानकारी देना पूर्व सीएमओ को पड़ा भारी, हुए निलंबित

इंजिनियर को कारण बताओ सूचना पत्र हुआ जारी

माही की गूंज, पेटलावद।

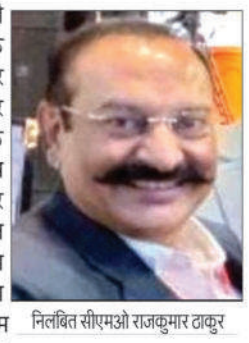
निलंबित सीएमओ राजकुमार ठाकुर

नगर परिषद पेटलावद में कुछ भी सही नही चल रहा ये बात तो जग जाहिर है और इसके प्रमाण भी धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। नगर परिषद के तत्कालीन सीएमओ राजकुमार ठाकुर को सीएम हेल्पलाईन में भ्रामक जानकारी देने की गलती करने पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कमिश्नर नीरज मंडलोई ने निलंबीत किया। लेखापाल राजकुमार ठाकुर को नगर परिषद पेटलावद का प्रभारी सीएमओ 3 अगस्त 2022 को बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उनके द्वारा सीएम हेल्पलाईन पर प्राप्त शिकायत क्र. 1000003304, 29 दिसम्बर 2022 में शिकायतकर्ता रतनबाई पति शांतिलाल गरवाल नगर परिषद पेटलावद अंतर्गत दर्ज सीएम हेल्पलाईन शिकायत 02 अप्रैल 2022 को पोर्टल पर दर्ज तत्थात्मक प्रतिवेदन भ्रामक स्वरूप रहे है। आदेश में बताया गया कि, 8 अप्रैल 2022 को शिकायकर्ता का जियो टेग छत स्तर का नहीं होने से द्वितीय किश्त का भुगतान होने में विलंब हो रहा है। शासन के निर्देशानुसार जियो टेग पूर्ण होने पर द्वितीय किश्त की राशि डाली जानी है। उक्त प्रतिवेदन वस्तु स्थिति से भिन्न एवं भ्रामक है। प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि, सीएम पोर्टल के विवरण अनुसार विभिन्न दिनांकों में बिना कार्यालय के दस्तावेजों के अवलोकन व स्थल निरीक्षण किये बिना टीम अंकित की गई है। साथ ही सूचना पत्र भी जारी किया गया किंतु रतनबाई पति शांतिलाल गरवाल की प्रविष्टि एमआईएस पोर्टल पर दर्ज नहीं किये जाने से यह स्थिति निर्मित हुई है। इस मामले में इंजिनियर दीपक वास्कले को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया। सात दिन में नोटिस का जवाब देना है।

सुबह कोहरे के आगोश में रहा अंचल, चली सर्द हवाएं

माही की गूंज, सारंगी।

ठंड के चलते दुकान से बहार बैठ कर धूप सकते दुकानदार

तेज सर्द हवाओं ने अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया है। कोहरे के साथ हुई सुबह के साथ पुरा ग्राम कोहरे के आगोश में रहा। सर्द हवाएं चल रही है सुबह के समय वाहन चालकों को अपने वाहन की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। दिनभर ठंडी हवाएं चलती रही, शीतलहर चलने से लोग ठिठुरते हुए नजर आए लगातार बढ़ रही सर्दी ने लोगों की दिनचर्या को बदल दिया है। सर्दी वाले मौसम के कारण खासकर बच्चे एवं बूढ़े के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। बच्चे जहां खांसी -सर्दी की चपेट में आ रहे हैं वही बुजुर्गों को भी परेशानी हो रही है। दिन भर बाजार सुने रहे, लोग ऊनी वस्त्र पहनकर धूप में बैठे रहे। बढ़ रही सर्दी के देखते हुए, किसानों का कहना है इस सर्दी में फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा गेहूं- चने की फसल अच्छी होने के आसार नजर आ रहे हैं। ठंडी के चलते लोग अलाव जलाकर सेक ले रहे है।

मुख्यमंत्री द्वारा समाधान ऑनलाइन विडियो कान्फ्रेंसिंग ली गई

प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में तत्परता से कार्यवाही कर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर मुख्यमंत्री द्वारा कनिष्ठ एवं खाद्य आपूर्ति विभाग अधिकारी प्रियंका अग्रवाल को बधाई दी गई

माही की गूंज, झाबुआ।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन में प्रदेश के विभिन्न नागरिकों की लंबित समस्याओं का समाधान करवाया और अधिकारियों को निर्देश दिए। समाधान ऑनलाइन में प्रकरणों के निराकरण के बाद सीएम हेल्पलाइन को प्राप्त होने वाली शिकायतों और निराकरण की कार्यवाही की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री चौहान ने श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिलों को बधाई देते हुए अन्य जिलों को भी नागरिकों की समस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री द्वारा विभागों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई। प्रदेश के उच्च प्रदर्शन वाले 5 विभागों में सामाजिक न्याय, ऊर्जा, गृह, परिवहन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग शामिल हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने इन जिलों के कलेक्टर्स और अन्य अधिकारियों को अच्छे कार्य निष्पादन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री चौहान ने अन्य विभागों से भी जन-समस्याओं को जल्द हल करने की अपेक्षा की। प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में तत्परता से कार्यवाही कर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर झाबुआ से कनिष्ठ एवं खाद्य आपूर्ति विभाग की अधिकारी सुश्री प्रियंका अग्रवाल को मुख्यमंत्री ने बधाई दी।

समाधान ऑनलाइन में आई शिकायत से शिकायतकर्ता के प्रकरण में निराकरण के साथ ही 723 अन्य हितग्राहियों को भी विवाह सहायता की राशि मिल गई। यह प्रकरण कुछ समय से लंबित थे। मुख्यमंत्री ने प्रकरणों में विलंब पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्रम विभाग को अभियान चला कर इस तरह के लंबित प्रकरण तत्काल हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की समीक्षा भी निरन्तर की जाये। इस दौरान झाबुआ से कलेक्टर रजनी सिंह, पुलिस अधीक्षक अगम जैन, सीईओ जिला पंचायत अमन वैष्णव एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

एफआईपीवी की तीसरी खुराक का शुभारंभ जिला चिकित्सालय में

माही की गूंज, झाबुआ। भारत शासन व मध्यप्रदेश शासन के दिशा निर्देशानुसार दिनांक 3 जनवरी 2022 को एफआईपीवी की तीसरी खुराक का शुभारंभ जिला चिकित्सालय झाबुआ के टीकाकरण केंद्र पर किया गया। एफआईपीव्ही की अतिरिक्त खुराक पूर्व की 6 सप्ताह व 14 सप्ताह के अतिरिक्त होकर पोलियो से डबल सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रारम्भ की गई है। अतिरिक्त तीसरी खुराक 9 माह से 12 माह की अवधि मे लगने वाले एमआर 1 व पीसीव्ही के बूस्टर खुराक के साथ दी जायेगी। उक्त टीकाकरण केंद्र पर डॉ जयपाल सिंह ठाकुर सीएमएचओ, डॉ बीएस बघेल सिविल सर्जन ,डॉ राहुल गणावा जिला टीकाकरण अधिकारी, श्री सत्यनारायण सोनी सुपरवाइजर, श्रीमती मंगला सोनी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, श्री शशिकांत पासवान एमपीव्हीएचए, श्री प्रेम सिंह कटारा, आशाकार्यकर्ता कमला फॉसिस, नर्सिंग स्टूडेंट किरण, रीती, सुनिता, कविता, यामिनी व अन्य स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ माताओं बच्चों के साथ उपस्थित रहे।

सांसद निधि से किये टैंकर वितरण

माही की गूंज, काकनवानी।

ग्राम पंचायत काकनवानी मंडल के अंतर्गत 22 पंचायत आती है। जिसमें से ग्राम पंचायत काकनवानी, भीमपुरी, वट्ठा, हरीनगर, बालवासा, पलासडोर, चिकल्या ,मोरझरी, हेड़ावा, पांच खेरिया ,गोरिया खानदान ,बिहार आदि 12 पंचायतों में सरपंच-सचिव को टैंकर सुपुर्द किए। जिनमें शेष बचे 10 पंचायतों में टैंकर वितरण किया जाना है।

टैंकर वितरण के लिए झाबुआ-रतलाम सांसद गुमानसिंह डामोर किसी कार्य की व्यस्तता के कारण नहीं आना बताया। जिस पर सांसद, सचिव सागर रावत एवं भील सेवा संघ के अध्यक्ष अजय डामोर, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य लक्ष्मणसिंह नायक, सांसद प्रतिनिधि दिलीप कटारा, पूर्व जिला महामंत्री श्याम ताहेड, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मक्कन डामोर, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बंटी डामोर एवं राजेश वसुनिया की उपस्थिति में टैंकर वितरण किए गए। इस मौके पर पलवाड क्षेत्र के समस्त पंचायतों के पंच-सरपंच, सचिव एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

भाजपा जिला अध्यक्ष ने किया निर्माणाधीन डेम का निरीक्षण

माही की गूंज, काकनवानी।

जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत निर्माणाधीन डेम पर पहुंचे, भाजपा जिला अध्यक्ष भानु भूरिया। जहां डेम नियमानुसार नहीं बनाकर भारी भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ गया। भ्रष्टाचार यहां तक की इस डेम की लंबाई, ऊंचाई व चौड़ाई कई मीटर कम कर दी गई। इस डेम की बॉडीवाल की लंबाई 262 मीटर की जगह 253 मीटर बनाई गई यानी पूरी 9 मीटर कम बनाई गई।

लेफ्ट साइड गुजरात तरफ की वाल जमीन से ऊपर तक 45 मीटर दीवार बनानी थी, जो मात्र 6 पाइंट 80 मीटर बनाई गई। तो दूसरी ओर मध्यप्रदेश की बॉर्डर पर वॉल बाउंड्री 24 पाइंट 18 मीटर की जगह मात्र 7 मीटर ही बनाई गई। बड़ी ही लापरवाही एवं भ्रष्टचारी से डेम का सारा भुगतान ठेकेदार एवं इंजीनियर ने करवा लिया।

भाजपा जिलाध्यक्ष भानु भूरिया को इस बात की शिकायत मिलने पर अपनी टीम में थांदला जनपद अध्यक्ष पति जालम डामोर, बलवासा सरपंच मनु डामोर ,वरिष्ठ नेता मलसिंह डामोर, कमलेश दतला, बोरी मंडल अध्यक्ष ज्ञानसिंह मोरी, भाजपा जिला महामंत्री राहुल पंचाल के साथ एक टीम बनाकर इस भ्रष्टाचार से बने डेम का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां और भी कई चीजें उजागर हुई एवं गंभीर लापरवाही और कमियां देखी गई....

1-निर्माण किए गए बैराज की वाल (दीवार) 4,5 जगह से क्रेक हो चुकी हैं, जो कि बांध निर्माण में घोर लापरवाही की गवाही स्वतः दे रही हैं।

2- बिना किसी लिखित आदेश के कार्यपालन यंत्री और अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग थांदला द्वारा अपनी मनमर्जी से तकनीकी नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

3-साइट पर पूर्ण निर्मित वाल पर सरिये ऊपरी लेयर पर ओवर लेप के लिए न होने से नए सरिये होल करके डलवाए जा रहे है जो की बांध निर्माण के नियमों के विरुद्ध है। कॉन्क्रीट तोड़े बगेर सरिये को ओवरलैप नहीं कर सकते तथा सरिये को डेम की मजबूती के लिए पुराने सरिये को नए सरिये से बाधंना बहुत आवश्यक है। ड्रिल करके सरिये अंदर नए डाल सकते है किन्तु पुराने सरिये से बांधा नही जा सकता है।

4-कार्य स्थल पर साइट इंजीनियर द्वारा बताया गया कि, ऐसा करने के निर्देश कार्यपालन यंत्री मैडम ने मौखिक रूप से दिए है। किन्तु लिखित में कोई आदेश जारी नही किया है। ऐसा प्रतीत होता हैं यह सब भ्रष्टाचार का खेल विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से चल रहा है।

5-स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बताया गया है कि, उक्त बांध की साइट तय स्थान से बदल दी गई हैं और निर्माण लम्बाई कम कर दी गई है, जिसका भुगतान भी विभाग द्वारा ठेकेदार को कर दिया गया है।

भानु भूरिया ने बताया कि, इस डेम के निर्माण गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भौपाल पहुंच कर अवगत करवाया जाएगा, ताकि इस बैराज के निर्माण की कमियों का पता चल सके और दोषी अधिकारियों और निर्माणकर्ता ठेकेदार पर कठोर कार्रवाई हो सके।

अर्थ पिशाच थाना प्रभारी को शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने हटाया

माही की गूंज, थांदला।

वर्ष 2022 अपनी खट्टी-मीठी यादों को सहौते हुआ विदा होकर आम जनमानस के जेहन में कई सवाल छोड़ बीत गया, जिसे समझ पाना कठिन होगा। वर्ष 2022 नगर की राजनीति के साथ प्रशासनिक क्षेत्र में भी उथल-पुथल भरा रहा। वर्ष 2023 में संपन्न होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल, भाजपा लंबे समय से पदस्थ प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों की सर्जरी में लगी दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान थांदला थाने में प्रथम बार महिला टीआई के रूप में पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने इस उम्मीद के साथ कौशल्या चौहान को थाना प्रभारी बनाकर थांदला भेजा था कि, वह जनमानस में अपनी छाप छोड़ते हुए अपराधों व अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने में सफल साबित होगी। किंतु अर्थ पिशाच थाना प्रभारी ने अपनी आमद के साथ भ्रष्टाचार, भांजगढ़ी प्रथा, नगर में अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों को श्रेय देती रही। विदित हो कि, पूर्व में राणापुर थाने में पदस्थ के दौरान राणापुर के युवा ने थाना प्रभारी की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। जिस पर आक्रोश के चलते ग्रामवासियों व परिजनों के विरोध के कारण इसे हटाकर लाइन हाजिर कर दिया गया था। उक्त कांड के चलते अपनी वर्दी खतरे में दिखाई देने के कारण थाना प्रभारी कौशल्या चौहान पर धारा 306 का मामला पंजीबद्ध किया गया था। जिसे थाना प्रभारी ने मृतक के परिजन से समझोता कर उक्त प्रकरण को रफा-दफा कर दिया। लाइन हाजिर रहते हुए लंबे अंतराल के बाद पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने कौशल्या चौहान को थाना प्रभारी के रूप में थांदला थाने पर पदस्थ किया था। थाना प्रभारी ने अपने जन्मदिन पर एक मादक पदार्थ तस्कर के हाथों गुलदस्ता लेकर स्वयं की वास्तविक छवि को प्रर्दषित किया था, यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुई थी। साथ ही शराब के ठेकेदारों को थाने पर बुलाकर महीना बंदी बढ़ाने की मांग कर तथा अन्य पुलिसकर्मियों व प्रिंट मीडिया के लोगों को कोसने का काम कर, यह थाना प्रभारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर पुलिस छवि को धूमिल करती रही। थाना प्रभारी के प्रश्नों के चलते एक वृद्ध एसआई को कार्य की प्रताड़ना व मानसिक तनाव के चलते हृदयाघात होने के कारण वह दुनिया छोड़कर चले गए। भ्रष्टाचार की गंगा में गोते लगाने में माहिर कौशल्या चौहान ने आईएसओ थाने का अवार्ड लेकर स्वयं के हाथों अपनी पीठ थप-थपा ने का कार्य किया है। साथ ही मादक पदार्थ के विरुद्ध शासन द्वारा चलाई गई मुहिम में खेतों से गांजे के पौधे जप्त कर, आला अधिकारियों की नजरों में बोने कद की थाना प्रभारी स्वयं को बड़ा साबित करने लगी। साथ ही नगर में जुआ-सट्टा, मादक पदार्थों के साथ अपराधियों के हौसले थाना प्रभारी के कार्यकाल में और अधिक बुलंद होते रहे।

टी आई कोशल्या चौहान का फोटो लगाना है।

अवैध शराब के नाम पर लूटते रहे

नगर व आसपास ताड़ी व शराब जब्ती के नाम पर कम मात्रा में मुकदमा दर्ज कर लोगों से रूपये एठने में माहिर थाना प्रभारी की शिकायत प्रिंट मीडिया व सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों ने मौखिक व लिखित में प्रमाण की शिकायत भोपाल से लगाकर झाबुआ तक की, तब जाकर भ्रष्ट थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक ने हटाया। विदित हो की इसी थाना प्रभारी कौशल्या चौहान ने नगर से 4 किलोमीटर दूर ग्राम छोटी धामनी के तड़वी के साथ शराब के नाम पर 65 लीटर शराब जप्ती बताकर उस तड़वी पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल की सलाखों में भेजा गया था। जिससे मानसिक प्रताड़ना व आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करते हुए उसे हाईकोर्ट से जमानत भी करवाना पडी। जबकी उसके परिवार के यहां से महज 5 लीटर देषी शराब जप्त की थी। साथ ही पानी की केन को भी शराब की केन बताकर 65 लीटर से अधिक शराब जप्त करना बताकर उस तड़वी पर झुठा मुकदमा लादा गया था।

प्राचार्य की प्रताड़ना : तंग आकर अतिथि शिक्षक ने छोड़ी नौकरी

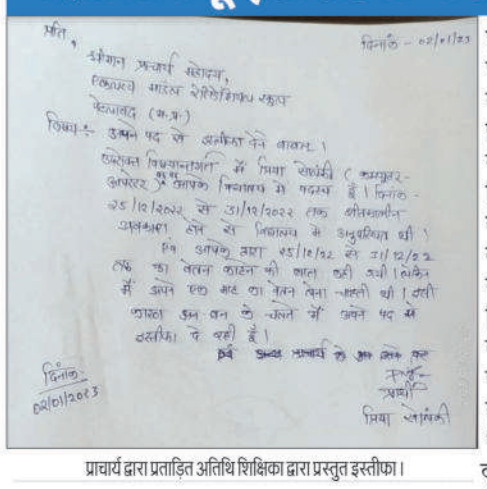

एकलव्य स्कूल के प्राचार्य की अजीबो-गरीब शर्त, कहा जब तक मैं प्राचार्य हूं इस संस्था में आवेंदन नहीं करोगी ऐसा लिखित में दो

प्रति,
श्रीमान प्राचार्य महोदय,
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
पेटलावद (म.प्र.)
विषय:- अपने पद से इस्तीफा देने बाबत।
उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं प्रिया सोलंकी (कम्प्यूटर-ऑपरेटर) आपके विद्यालय में पदस्थ हूँ। दिनांक 25/12/2022 से 31/12/2022 तक शीतकालीन अवकाश होने से विद्यालय में अनुपस्थित थी। फिर आपके द्वारा 25/12/22 से 31/12/22 तक का वेतन काटने की बात कही गयी। लेकिन मैं अपने एक माह का वेतन लेना चाहती थी। इसी कारण इस बात के चलते मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ।
दिनांक - 02/01/23
दिनांक 02/01/2023
प्रार्थी
प्रिया सोलंकी

प्राचार्य द्वारा प्रताड़ित अतिथि शिक्षिका द्वारा प्रस्तुत इस्तीफा।

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

विकास खण्ड का एकलव्य शिक्षा परिसर, एक बार फिर सुर्खियों में आया है। यहा एक अतिथि शिक्षिका ने प्राचार्य की प्रताड़ना से परेशान होकर नोकरी से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। इस दौरान प्राचार्य और शिक्षिका के बीच रिकॉर्डिंग भी सामने आई। जिसमे प्राचार्य ओमकारसिंह मैड़ा, अतिथि शिक्षिका से इस्तीफा लेते समय एक शर्त लिखवाते सुनाई दे रहे। जिसमे प्राचार्य ने अतिथि शिक्षिका से कहा कि, वो जब तक इस संस्था में दोबारा नोकरी के लिए आवेंदन नही करेगी जब तक वो इस संस्था में प्राचार्य है। बातचीत के दौरान अतिथि शिक्षिका रोती-बिलखती रही पर प्राचार्य ने एक नही सुनी। प्राचार्य संस्था के काम करवाने के लिए क्रिसमस की छुट्टीयो में भी मेडम पर संस्था में आने का दबाब बना रहे थे। मेडम की माने तो प्राचार्य छुटियो के दौरान बिना टाइम के फोन कर परेशान कर काम करने का दबाव बना रहे थे। जिससे परेशान होकर मेडम को प्राचार्य का नम्बर ब्लैकलिस्ट तक करना पड़ा। बाद में नियम के विरुद्ध जाकर छुट्टियों का वेतन काटा गया, जबकि शासन के ऐसे कोई निर्देश नही है। बातचीत में ये भी सामने आया कि, प्राचार्य अतिथि शिक्षिका को नोकरी पर लगाने के लिए बार-बार उन पर एहसान जताने की बात करते थे, जिससे महिला शिक्षिका खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। लगातार काम और वेतन काटने के दबाब के साथ अपमान होने से क्षुब्ध अतिथि शिक्षिका को आखिरकार नोकरी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।

स्कूल शिक्षा विभाग ने घोषित किया था, 25 से 31 दिसम्बर तक का अवकाश

मध्यप्रदेश शासन के स्कूल एवं शिक्षा विभाग द्वारा 24 दिसम्बर 2022 को प्रारित आदेश क्रमांक एफ 40-04/2019/20-2 के अनुसार स्कूल के समस्त शिक्षकों और बच्चों का अवकाश 25 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक घोषित किया था। जिसके दायरे में अतिथि शिक्षक भी आते हैं। बावजूद इसके प्राचार्य द्वारा छुट्टियों में महिला अतिथि शिक्षक पर काम का दबाव बनाया, जिसके लिए बाध्य करना नियम के विपरीत है। प्राचार्य और शिक्षिका के बीच की बातचीत की रिकॉर्डिंग है, उसमें प्राचार्य कहते हुए नजर आ रहे हैं कि, छुट्टियों के बाद भी उन्हें भी काम करना पड़ रहा है और हम भी काम कर रहे हैं। कम्प्यूटर शाखा महत्वपूर्ण है और जानकारी बनाने के लिए आना पड़ेगा। अतिथि शिक्षिका इस बात को लेकर प्राचार्य से छुट्टियों के बाद जानकारी बनाने की बात कह रही है। अतिथि शिक्षिका के अनुसार संस्था में छुट्टियों के दौरान 3 पुरुषों (प्रिसिपल,बाबू व आफिस अस्सिटेंट) और 3 चपरासी के स्कूल में होने पर एक अकेली महिला को शीतकालीन अवकाश में बुलाया गया था, जो मुझे मेरी सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नही लगा, इसलिए मैंने जाना ठीक नही समझा। जबकि कम्प्यूटर शाखा में दो और भी लोग है, लेकिन सिर्फ मुझे ही बुलाया गया।

राज्यपाल के दौरे पर सुर्खियों में आया था एकलव्य परिसर

गत वर्ष प्रदेश के राज्यपाल माननीय मांगू भाई पटेल जिले के दौरे पर थे। इस दौरान राज्यपाल एकलव्य स्कूल पेटलावद पहुचे थे। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्राओं ने छात्रावास की अव्यवस्था को सार्वजनिक रूप से राज्यपाल के सामने रखा था। जिसके बाद होस्टल अधिक्षका और वर्षो से पेटलावद में जमे बैठे विवादित प्राचार्य प्रसाद को हटाया गया था। पूरे मामले में जमकर राजनीति हुई, जिले के पूर्व कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी पर भी गम्भीर आरोप लगे। लेकिन मामला परिसर तक सीमित रहा और प्राचार्य को हटाने और वही रखने के तीन अलग-अलग आदेश जारी हुए, जिससे प्रदेश के भ्रष्ट सिस्टम की बडी पोल खुल गई थी।

क्युआर कोड स्केन कर सुने प्रार्चय की मनमानी।

पूर्व में भी राज्यपाल के दौरे पर सुर्खियों में आ चुका है एकलव्य शिक्षा परिसर, आज भी नियम विरुद्ध हो रहा काम

हालांकि लोगो को उम्मीद थी कि, इस पूरे प्रकरण के बाद स्कूल की व्यवस्था सुधरेगी ओर बहुत कुछ सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नही हुआ। आज भी संस्था विवादित ओर भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके मामले लगातार सोशल मीडिया और 181 की शिकायतो के माध्यम से बाहर आ रहे हैं।

फर्जी भर्ती सहित ज्यादातर शिक्षक नियम विरुद्ध लगे हुए है संस्था में

एकलव्य शिक्षा परिसर में आज भी भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। संस्था में कार्यरत अधिकांश शिक्षक नियम के विरुद्ध इस संस्था में कार्य कर रहे है, जो नियम के अनुसार इस संस्था में काम करने के लिए पात्र नही है। ये ही नही परिसर के होस्टल में पदस्थ अधिक्षक भी यहां कार्य के लिए पात्र नही है। उल्टा एक अतिरिक्त शिक्षिका की भर्ती होस्टल अधिक्षका के साथ की गई। जो अपने आप मे भ्रष्टाचार का खुला सबूत है, क्योंकि इस प्रकार की भर्ती का कोई प्रावधान नही है। दूसरी और अतिथि शिक्षकों को लेकर भी इस संस्था में बड़ा मामला सामने आया है जिसकी जांच की जाए तो पता चल जाएगा कि, किस तरह से विशेष लोगो को लाभ देने के लिए पात्र लोगो की अनदेखी कर उनको पीछे किया गया। ये सब हो रहा है शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी से लेकर प्राचार्य की मिलीभगत से जो खुद के भ्रष्टाचार उजागर न हो इसलिए ऐसी भर्ती कर रहे हैं, जो समय आने पर राजनीतिक रूप से लाभ दे सके।

एकलव्य शिक्षा परिसर पेटलावद।

अतिथि शिक्षकों के छुट्टियों का वेतन काटने का प्रावधान नही

मामूली वेतन पर कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों का वेतन काटने का कोई प्रावधान नही है। अतिथि शिक्षक को उसकी संस्था में 20 दिन से अधिक कार्य दिवस होने पर शासकीय छुट्टियों का वेतन नही काटने का प्रावधान है। लेकिन लगातार देखने मे आ रहा है कि, संस्था प्रमुख कार्य दिवस के अनुसार वेतन देने के नाम पर अतिथि शिक्षकों को प्रताड़ित करते हैं और उनके वेतन में स्वयं का हिस्सा खोज लेते हैं। सरकारी रिकॉर्ड के आकड़े में ये सपष्ट है कि, अलग-अलग संस्थाओं में पदस्थ अतिथि शिक्षिकों को एक जैसे काम के बाद भी अलग-अलग वेतन दिया गया है, जो जांच का विषय है। अन्य संस्थाओं के मुकाबले एकलव्य परिसर में अतिथियों का वेतन अच्छा है, जिसके चलते जनप्रतिनिधियों की नजर यहां रहती है और अपने करीबी रिष्तेदारो को यहां जेम-तेम फिट कर देते हैं। जिसके बदले संस्था से जुड़े भ्रष्ट को संरक्षण रूपी रिश्वत परोसी जाती है, जिसके दम पर भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा और हेराफेरी होती हैं। इस मामले के उजागर होने के बाद भी प्राचार्य पर कार्रवाई हो या भविष्य निर्माता, ऐसी संस्थाओं की स्थिति सुधरेगी ये कहा नही जा सकता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान उनके भ्रष्टाचार मुक्त देश-प्रदेश के दावे केवल कागजी है। ये तय है, क्योंकि उनके ही शासन में प्रशासन और पार्टी के लोग, गले-गले तक लिप्त होकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।

गिट्टी क्रेशर में अंधाधुन ब्लासिंटग से तीनों भवनों में आई दरारें

ब्लासिंटग होती है हिल जाता है पूरा भवन, एबीवीपी ने सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज, झाबुआ।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झाबुआ ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के नाम तहसीलदार रानापुर को ज्ञापन सौंपा। विभाग संयोजक झाबुआ प्रताप कटारा ने ज्ञापन में बताया कि, शासकीय महाविद्यालय राणापुर एवं शासकीय सीनियर बालक छात्रावास क्रमांक 1,2 रानापुर के निकट लगभग 85 मीटर की दूरी पर गिट्टी क्रेशर मशीन है, जिसके ब्लासिंटग से तीनों भवनों मे दरारे आ गई है और जब भी ब्लासिंटग होती है पूरा भवन हिलता है। सीनियर बालक छात्रावास क्रमांक -2 के पिछले हिस्से की दो खिड़कियों के शीशे भी ब्लासिंटग के दौरान टूट गए हैं तथा पत्थर भी आसपास गिरते है। धूल बहुत उड़ती है जिससे छात्रों को काफी समस्या होती है। उक्त गिट्टी क्रेशर मशीन को बंद किया जाना चाहिए नही तो छात्रावास के बच्चों के साथ कभी भी अनहोनी घटना हो सकती है। तथा छात्रावास में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, प्रतिदिन 200 छात्रों के लिए चार टैंकर पानी क्रय कर पूर्ति की जा रहा है जिसका भुगतान आज दिनांक तक शासन स्तर से नहीं हुआ है। इसलिए उक्त छात्रों हेतु जल आपूर्ति के लिए कुंआ खनन की आवश्यकता है। ज्ञापन में छात्रों की विभिन्न समस्याओ पर भी शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया गया कि, भवन शहर से लगभग 2 कि.मी दूरी पर है। सुरक्षा की कोई व्यवस्था नही है, बाउंड्री वाल निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है। बालक सीनियर छात्रावास के विद्यार्थी 5 कि.मी पैदल चलकर माडल स्कूल में अध्ययन करने जाते हैं। उन विद्यार्थियों को जाने-आने में कई समस्याएं आती है, विद्यार्थियों के लिए बस की व्यवस्था की जाएं।

एबीवीपी के जिला संयोजक निलेश गणावा ने कहा कि, 7 दिनों के अंदर मांगे पूरी नहीं होती है, तो विद्यार्थी परिषद व छात्रो द्वारा कलेक्टर कार्यालय झाबुआ का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी।

बार-बार विभाग में स्थानतरण से जिला पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली पर उठ रहे है सवाल

माही की गूंज, बामनिया।

झाबुआ पुलिस अधीक्षक आगम जैन पुलिस व्यवस्था में फेरबदल करते हुए 2 महीने भी पूरे नही हुए की पीएस डामोर का तबादला मदरानी चौकी पर किया गया और अशोक बघेल को बामनिया चौकी नया प्रभारी बनाया गया। अशोक बघेल पूर्व में पेटलावद थाना, सारंगी चौकी और खवास चौकी पर पदस्थ रह चुके है। वही 3 महीनों में यहा 2 बार चौकी प्रभारी बदले गए, इस फेरबदल से जिला कप्तान की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे है। वेसे बामनिया में अवैध काम धड़ल्ले से चलते है जैसे ढाबे पर अवैध शराब बेचना, सट्टा चलाना ये काम भी पुलिस की नाक के नीचे ही होता है, सटोरिये पुलिस को ऊपर तक मासिक बंदी देने का दावा करते है। नरेश निनामा के बाद चौकी प्रभारी श्याम कुमावत ने कार्यभार संभाल था चौकी प्रभारी ने आते ही अवैध धंधे करने वालो पर कार्यवाही कर अवैध धंधे जैसे सट्टा और अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाई थी। उनके कार्यकाल में सारे अवैध धंधे बंद हो गए थे, लेकिन उनका स्थान्तरण भी 1 महीने में झाबुआ हो गया। उसके बाद फिर से अवैध कारोबार बामनिया में फिर से फल-फूल रहा है। अब देखना ये है कि, नवागत चौकी प्रभारी अशोक बघेल कितने समय चौकी प्रभारी रहेंगें और अवैध धंधो से कैसे निपटगे यह बड़ी चुनोती है।

पुर्व चौकी प्रभारी पीएस डामोर

नवागत चौकी प्रभारी अशोक

श्रमिक राज्य से बाहर जाते हैं तो पंजीयन अनिवार्य रूप से होः उड़के

माही की गूंज, झाबुआ। मध्यप्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग के अध्यक्ष भागचंद उड़के एवं सदस्य विनोद रिछारिया द्वारा कोरोना कार्यकाल एवं उसके पश्चात कार्य हेतु प्रवास पर गये श्रमिकों, उनके परिवारों के सदस्यों से कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे विस्तृत चर्चा की गई। जिले के श्रमिकों को शासन के प्रावधानों के अनुसार योजनाओं का प्रावधानों के अनुसार योजनाओं का लाभ दें। यह बात बुधवार को राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग के अध्यक्ष भागचंद उड़के और सदस्य विनोद रिछारिया ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कही। जिले के श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों, सदस्यों तथा श्रमिकों से उनके हित में और बेहतर प्रावधान किए जाने के लिए फीडबैक लिया, जो शासन को सौंपा जाएगा। उड़के ने कहा श्रमिकों के हित में संबल तथा अन्य संचालित योजनाओं की जानकारी का प्रसार श्रमिक वर्ग में हो, उनमें जागरूकता उत्पन्न रहे। राज्य से बाहर जाते हैं तो उनका पंजीयन अनिवार्य रूप से हो, जो पंचायत में किया जाना चाहिए। श्रम विभाग की जितनी भी योजनाएं है, उनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये। जिससे श्रमिक शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ले सके। आयोग के सदस्य रिछारिया ने कहा प्रवासी श्रमिक का पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए, जिससे उनको लाभ तो मिलेगा ही कई परेशानियों से भी सुरक्षित रहेंगे। प्रवासी श्रमिक शोषण के विरूद्ध सतर्क रहें आत्मबल से कार्य करें।

ऑपरेशन हेलो के तह्त 105 गुम मोबाइल ट्रेस कर लौटाये

माही की गूंज, झाबुआ।

जिला पुलिस झाबुआ की सायबर टीम ने गुम हुए 105 मोबाइल तकनीकी माध्यमों से ट्रेस कर बरामद करने में सफलता पाई है। मोबाइल घुमने संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस अधीक्षक झाबुआ अगम जैन के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे के मार्गदर्शन में साइबर सेल की टीम द्वारा ÷ऑपरेशन हेलो÷ के तहत अगले चरण में गुम मोबाइलों को सर्चकर उनका पता लगाकर विभिन्न कंपनियों के कुल 105 मोबाइल बरामद किये है। जिनकी अनुमानित कीमत 14 लाख रूपये है। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से आह्वान किया कि, मोबाइल पर इंटरनेट का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। साथ ही अपने मोबाइल के लॉक व गोपनीयता की जानकारी किसी से शेयर ना करें। उक्त सराहनीय कार्य पर साइबर सेल झाबुआ की टीम आरक्षक 98 मंगलेश पाटीदार, 552 महेश प्रजापति, 573 संदीप बघेल एवं आर. 192 दीपक पटेल को पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई।

डिजिटल बूथ के जरिये मैदान में उतरना भारी न पड़ जाए भाजपा को

कही पे निगाहें कही पे निशाना तर्ज पर चल रहा एप्प, नाम किसका काम किसका

माही की गूंज, झाबुआ/पेटलावद

भाजपा के संगठन में लगातार कोई न कोई कार्य चलता रहता है, कारण है कार्यकर्ता जुड़े रहे साथ ही नए कार्यकर्ता जोड़े जा सके। जमीन स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने की लगातार प्रयासरत रहने वाली भाजपा ने बढ़ते डिजिटलाइजेशन को भी संगठन को मजबूत करने का आधार बनाया है। भाजपा ने बूथ स्तर पर कार्य करने के लिए संगठन 2.0 संगठन गढ़े चलो एप्प शुरू किया। जिसके जरिये बूथ स्तर पर काम करने की योजना है। शहरी क्षेत्र में तो इस एप्प को सफलता मिल सकती है, लेकिन ग्रामीण इलाको में इस एप्प को लेकर तैयारियां उस स्तर की नही दिख रही है। विगत दिनों इस एप्प को लेकर कार्यकर्ताओ को जानकारी दी गई, लेकिन एप्प को लेकर कार्यकर्ता संतुष्ट नही है।

कही पे निगाहे कही पे निशाना तर्ज पर चल रहा एप्प, नाम किसका काम किसका

कागजो पर काम को लेकर फिलहाल भाजपा के आंकड़े उस स्तर के नही है, जैसे संगठन ने तय किये थे। वही दूसरी ओर डिजिटल प्लेटफार्म पर संगठन को तैयार किया जा रहा है। विगत दिनों जिलाध्यक्ष भानु भूरिया के नेतृत्व में डिजिटल बूथ की बैठक आयोजित की गई, बैठक में उन सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया जो कागज पर बूथ अध्यक्ष या सयोंजक बनाये गए हैं, लेकिन जब पासवर्ड ओर आईडी डाल कर एप्प खोला गया तो उस पर नाम दूसरे कार्यकर्ता का आ रहा है। मतलब एप्प के लिए जो जमीन पर काम कर जानकारी भेजेगा उसका कोई अता पता नही होगा और नाम उसका होगा जो एप्प पर दर्ज है। बताया जा रहा है इस कारण कई कार्यकर्ताओ ने इस एप्प पर जब तक काम नही करने का बोल दिया जब तक उनके नाम की आईडी नही खुलती । फिलहाल ये हालत शहरी क्षेत्र की है तो, ग्रामीण इलाकों में क्या हालत होगी भाजपा के इस डिजिटल एप्प की।

संगठन 2.0
संगठन गढ़े चलो

खानापूर्ति के लिए डाल दिए गए थे नाम

पूर्व जिलाध्यक्ष नायक के कार्यालय में डिजिटल बूथ स्तर की जानकारी अपलोड करने का कार्य हुआ था। लेकिन कई मण्डल के अध्यक्षों ने खानापूर्ति के लिए जानकारी अपलोड कर दी, जिसमे कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको जानकारी तक नही की उनका काम क्या है। जो चुनाव के आने से पहले परेशानी का सबब बनना तय है। क्योंकि भाजपा के संगठन को इस एप्प के माध्यम से डिजिटल प्लेटफार्म कर, कार्य शुरू करने की व्यू रचना एक बार फिर से करनी होगी ।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले चुकी देवांशी का स्वागत

माही की गूंज, पेटलावद। खेलो इंडिया में चयनित व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपने हरफन मौला प्रर्दशन करने वाली बिटिया देवांशी चौधरी का नगर आगमन पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष सोनू विश्वकर्मा एवं जिला उपाध्यक्ष आशीष बाविस्कर एवं राजू निनामा उपस्थित रहे। जिला उपाध्यक्ष आशीष बाविस्कर ने बताया कि, जिले में ऐसे कई प्रतिभाएं हैं जो खिलाड़ी के रूप में अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बस उन्हें सम्मान की जरूरत है। इसी तरह हम खिलाड़ियों का सम्मान करते रहे, ताकि वह अपने खेल को और निखार कर जिले और नगर का नाम रोशन करते रहे। इसी अपेक्षाओं के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की।

संपादकीय

प्रशासक के प्रयासों पर पानी फेरती आतंकवादी घटनाएं

पाक सीमा से लगे जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में हाल की लक्षित हत्याएं इस केंद्र शासित प्रदेश में गंभीर होती स्थिति को दर्शाती हैं। रविवार को डांगरी गांव में फायरिंग में चार लोगों की हत्या व कई लोगों के घायल होने से देश सहमा हुआ था कि, अगले दिन इसी गांव में बम धमाके से हुई एक बच्चे की मौत ने आतंकवादियों के दुस्साहस की बानगी दिखा दी। आतंकवादियों ने गांव में आधार कार्ड देखकर लोगों को निशाने पर लिया और जमकर फायरिंग की। फिर अगले दिन आईईडी ब्लास्ट किया। ग्रामीणों का आतंकित होना स्वाभाविक है जब उन्हें घर में घुसकर मारा जा रहा हो। नि:संदेह, मामले में खुफिया सूचना व सुरक्षा चौकसी में कहीं न कहीं कमी जरूर रही है, जो आतंकी अगले दिन बम ब्लास्ट करने में कामयाब रहे। इससे कुछ सप्ताह पूर्व राजौरी में सेना के कैंप के बाहर दो लोगों की हत्या हुई थी। तभी सुरक्षा बलों की तरफ से चौकसी बढ़ा देनी चाहिए थी। यह भी गंभीर चिंता का विषय है कि ये घटनाएं उस राजौरी क्षेत्र में हुई हैं, जिसमें आतंकवादी घटनाएं कम ही देखने में आती थीं। हाल के महीनों में सार्वजनिक स्थानों पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के ट्रेंड के बजाए जिस तरह से संप्रदाय विशेष के लोगों को गोलियों का शिकार बनाया जा रहा है, वह एक गंभीर मसला है। यह जहां कानून-व्यवस्था की विफलता का मामला है वहीं केंद्र की उन नीतियों की सार्थकता पर सवाल उठाता है, जिसमें बड़े व्यवस्थागत बदलावों के बाद शांति स्थापना का दावा किया गया था। खासकर जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 की समाप्ति के बाद। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसे माहौल में राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापना के लक्ष्य हासिल हो पाएंगे...? जाहिर बात है कि, कभी कश्मीरी पंडितों तो कभी बाहरी कामगारों को निशाना बनाकर आतंकवादी जम्मू-कश्मीर में सांप्रदायिक विभाजन की साजिश रच रहे हैं। जिसमें उन्हें सीमापार से हथियार व अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर में अलगाव के प्रतीक बताए जा रहे विशेष दर्जे के समाप्त होने के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी केंद्रीय शासन में अलगाववादी ताकतों का शमन होगा। आतंक से मुक्ति के बाद आने वाली विकास की बयार से केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ सकेगा। नि:संदेह, केंद्र व केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के प्रयासों पर आतंकवादी घटनाएं पानी फेरती हैं। खासकर यूटी में चुनावी प्रक्रिया को मूर्त रूप देने के प्रयासों को भी इन घटनाओं से झटका लगेगा। उल्लेखनीय है कि, हाल के दिनों में विदेश मंत्री ने तमाम वैश्विक मंचों पर पाक के आतंकवादियों को संरक्षण देने के कुत्सित प्रयासों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। साथ ही यह भी कि आतंकवाद को प्रश्रय देना पाक के सत्ता प्रतिष्ठानों की रणनीति का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र में भी उन्होंने पाक को आतंकवाद का केंद्र बताया था। इसके बावजूद पाक पिछले सात दशक से भारत को लहूलुहान करने की साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। अपने कूटनीतिक स्वार्थों के पोषण के लिए अमेरिका जिस तरह का गेम खेल रहा है, उससे पाकिस्तानियों के हौसले बढ़े हैं। दुनियाभर में आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले अमेरिकी हुकमरान आखिर क्यों नहीं पाक को आतंकवादियों की मदद करने से रोकते। बीते वर्ष पाक के साथ एफ-16 को लेकर किया गया समझौता बताता है कि अमेरिका दोरंगी चाल चलकर पाक के निरंकुश मंसूबों को समर्थन ही दे रहा है। बहरहाल, इतना तय है कि जम्मू-कश्मीर में लंबित विधानसभा के चुनाव कराने के लिये शांति व्यवस्था बनाना जरूरी है। भारत को पाक के मंसूबों को समझते हुए उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मोर्चा खोल देना चाहिए। केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए कि सेना व सुरक्षा बलों की चाकचौबंद व्यवस्था के बावजूद यदि आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं तो समस्या की जड़ें कहां हैं...? यह भी कि लोगों की जनतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी के बाद आतंकवाद पर विराम लग सकेगा...? सबसे पहले तो लक्षित हत्याओं पर विराम लगाने की कोशिश होनी चाहिए।

अभी तैयार होना है अयोध्या को तीर्थ यात्रियों के लिए

शंभूनाथ शुक्ल

पिछले दिनों 31 दिसंबर और पहली जनवरी को अयोध्या में लगभग पांच लाख श्रद्धालु आए। यह सरकारी आंकड़ा है, कुछ लोग इसे आठ-दस लाख भी बताते हैं। सारे होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं भरी हुई थीं। बहुत से लोग मंदिरों में कोई कोना देख कर सो लिए। सरयू के घाटों पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर के लोग तो सुबह आए और शाम को लौट लिए, लेकिन जो लोग दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र व तमिलनाडु से आए थे, उनके लिए विवशता थी। इसकी एक वजह तो यह है कि सरकारी तौर पर यह कभी नहीं जारी किया जाता कि उत्तर के मैदानी शहरों और तीर्थों में नवंबर से फ़रवरी के बीच यात्रा नहीं करनी चाहिए। यहां तो यात्रा के लिए मार्च, अप्रैल अथवा सितम्बर, अक्तूबर ही सुहाने मौसम हैं।

अयोध्या का विकास तो बहुत हो रहा है। ज्यों-ज्यों मंदिर का निर्माण कार्य तेज हो रहा है, त्यों-त्यों उसकी चर्चा भी है। देश और विदेश के श्रद्धालु भगवान राम की नगरी अयोध्या में आने को आतुर रहते हैं। किंतु अयोध्या में ढंग के होटल नहीं हैं, गेस्ट हाउस सरकारी हैं और उनमें ठहरने के लिए आम पब्लिक को अनुमति नहीं है। रेलवे के रिटायरिंग रूम में भला कितने लोग ठहर सकते हैं। यह सब देख कर लगता है कि राम जन्मभूमि मंदिर का प्रचार तो बहुत अधिक हुआ है, पर वहां अभी व्यवस्थाएं अपेक्षित हैं। राम मंदिर निर्माण के पूर्व अयोध्या का विकास करना था। सरकार स्वयं या निजी हाथों में ज़मीन देकर होटलों का संचालन करवाती। उनकी दरें भी निर्धारित करती। अब अयोध्या में ज़मीन की लूट तो शुरू हो गई है, लेकिन इस ज़मीन पर न तो अब खेती हो रही है न निर्माण कार्य। कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और गुजरात के इन्वेस्टर ज़मीन ख़रीद कर छोड़ देते हैं, ताकि और महंगी होने पर उन्हें बेचा जा सके। किंतु इस ज़मीन का फ़िलहाल उपयोग क्या है? बेहतर होता सरकार खुद ज़मीन ख़रीद कर उसे विकसित करवा कर बेचती। इससे विकास समान रूप से होता। अभी तो हाल यह है, कि खेतिहर ज़मीन किसान बेच रहा है। कोई निर्धारित दर नहीं है। शहर के अंदर की ज़मीन दो से तीन हज़ार रुपये वर्गफुट है, और हाई-वे के किनारे-किनारे खेतिहर ज़मीन 50 लाख रुपये एकड़।

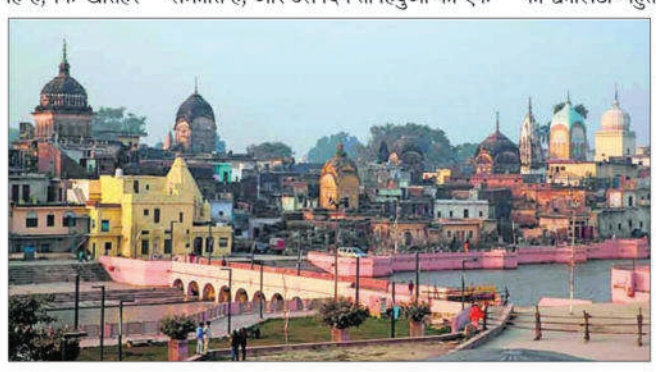

अभी राम मंदिर बनने में एक साल का तो समय लगेगा ही। खुद राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति से जुड़े लोग भी ऐसा मान रहे हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के ट्रस्टी राजा विमलेंद्र मोहन मिश्र ने बताया कि जनवरी, 2024 तक यहां गर्भगृह का निर्माण हो जाएगा तथा भगवान की प्राण-प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। लेकिन पूरा राम मंदिर परिसर कंप्लीट होने में समय लगेगा। जहां तक शहर के रास्तों का सवाल है, सड़क किनारे के लोग अपनी दुकानें और मकानों का कुछ हिस्सा स्वयं हटा रहे हैं। सरकार की तरफ़ से उन्हें उनका भुगतान भी किया जा रहा है। दरअसल अयोध्या को विकसित करने की योजना पूर्व में कभी बनाई नहीं गई, इसलिए अयोध्या की सड़कें और गलियां बहुत संकरी थीं। कुछ गलियों में से चार आदमी भी समानांतर नहीं चल सकते थे।

उधर पिछले तीन साल में आवाजाही खूब बढ़ी है। वीवीआईपी तो आते ही हैं, हर तीज-त्योहार में आम जनता भी उमड़ने लगती है। पुलिस-प्रशासन के अभी से हाथ-पांव फूले हैं कि 14 जनवरी को क्या होगा? जब 31 दिसंबर और पहली जनवरी को भीड़ इतनी अधिक थी तो 14 को तो मकर संक्रांति है, और उस दिन तो हिंदुओं का एक बड़ा पर्व है। पूरे देश से हिंदू जुटेंगे। इतनी सर्दी में इन श्रद्धालुओं को कहां रोका जाएगा, यह एक यक्ष प्रश्न है। पिछले कुछ वर्षों से विश्व के अन्य देशों में बसे हिंदुओं में भी अयोध्या, काशी, मथुरा, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारिका आदि तीर्थ-स्थलों की यात्रा का रुझान खूब बढ़ा है। काशी, मथुरा में तो पांच सितारा होटल भी हैं और सरकार ने भी यहां खूब विकास किया है। पुरी में तो विगत वर्षों में नवीन पटनायक ने वहां के पूरे क्षेत्र को पर्याप्त विकसित किया है। ख़ासकर मंदिर के मुख्य द्वार की सड़क तो सिक्स लेन की हो गई है। इसके अतिरिक्त पूरे पुरी क्षेत्र में पेयजल को इतना शुद्ध कर दिया गया है कि सड़क किनारे लगे नल के पानी (टेप वॉटर) को सीधे पी सकते हैं।

मगर अयोध्या आज की तारीख़ में पूर्ण रूप से अविकसित है। कुछ होटल हैं ज़रूर पर उन्हें रहने लायक़ भी नहीं कहा जा सकता। सरयू के तट पर राम पैड़ी बना कर सरकार ने इसे पिकनिक स्पॉट के तौर पर विकसित करने की कोशिश की है। लेकिन एक तो यहां खुली जगह कम है, दूसरे काम की क्वालिटी बहुत ख़राब है। फ़र्श में पत्थर उखड़े पड़े हैं। कोई छाया का प्रबंध नहीं है। सरयू के घाटों पर पानी नहीं है और उस तरफ़ तो इतनी गंदगी है कि पांव भी संभाल-संभाल कर रखना पड़ता है। राम की पैड़ी के क़रीब लता मंगेशकर चौक बनाया गया है। किंतु ठीक उसके ऊपर से हाई-टेंशन लाइन लाइन गुजर रही है और इस चौक के बीच में बने पार्क में पत्थरों से जो वीणा बनाई गई उसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि हाई टेंशन लाइन और उसके सिरे के बीच फ़ासला पांच फ़िट से भी कम का है।

अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए फ़ाइव स्टार होटल बनाने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत-से औसत दर्जे के होटल भी। लखनऊ से अयोध्या राजमार्ग को एक्सप्रेस वे बनाना होगा, जो कम से कम आठ लेन का हो। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी होना चाहिए, ताकि कंप्लीट राम मंदिर बनने के बाद यहां देश-विदेश से आने वाले यात्रियों को असुविधा न हो। यहां राम मंदिर के अतिरिक्त और भी सैकड़ों मंदिर हैं, उनके प्राचीन स्वरूप को संरक्षित करना होगा। हनुमान गढ़ी और कनक भवन (सीता जी का मंदिर) यहां के दो अत्यंत प्रतिष्ठित मंदिर हैं। लेकिन यहां तक पहुंचना बहुत दुष्कर है। गलियां संकरी हैं। हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों को आरामदायक बनाना आवश्यक है, इसके अतिरिक्त यहां एक लिफ़्ट होनी चाहिए, ताकि जो लोग सीढ़ियां चढ़ने में असुविधा महसूस करें, वे लिफ़्ट से मंदिर के गर्भगृह के निकट पहुंच सकें। यूं कनक भवन सुंदर बना है, लेकिन वहां तक पहुंचने का मोटर मार्ग ठीक किया जाए।

इसके अतिरिक्त अभी श्रद्धालुओं से यहां मनमाने दाम वसूली होती है। स्थानीय ई-रिक्शा वाले अंधाधुंध सवारी बिठाते हैं और आंख मूंद कर चलाते हैं, जिससे हर गली में कहीं न कहीं कोई रिक्शा पलट जाता है। ई-रिक्शा के लिए नियमों का निर्धारण भी होना चाहिए। वहीं स्थानीय परिवहन की कोई गाइड लाइन सरकार तय करे। यद्यपि अब फ़ैज़ाबाद ज़िले का नाम अयोध्या कर दिया गया है, लेकिन फ़ैज़ाबाद शहर में इंडियन मिलिटरी की डोगरा रेजिमेंट का मुख्यालय है, इसलिए अयोध्या को फ़ैज़ाबाद से पूर्णतया अलग कर इसे एक पृथक ज़िला बनाया जाए। इसके अधिकारी और पुलिस पुराने फ़ैज़ाबाद ज़िले से अलग हों। अयोध्या तीर्थ विकास प्राधिकरण बने। तब अयोध्या का त्वरित विकास होगा और अयोध्या विश्व मानचित्र पर उभरेगी।

विपक्षहीन लोकतंत्र....? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय....

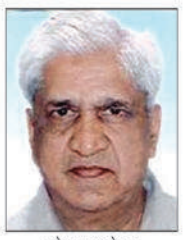

ओमप्रकाश मेहता
लेखक

दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हमारे भारत की आजादी की हम हीरक जयंती मना रहे हैं लेकिन क्या हमारे देश के मुख्य कर्णधारो ने कभी इस सच्चाई पर भी गौर किया कि बिना अधिकारिक या संवैधानिक विपक्ष के लोकतंत्र अधूरा है? हमारी आजादी के 75 सालों में से करीब 48 साल देश विपक्ष विहीन रहा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उनके नाती राजीव गांधी के शासन काल में भी विपक्ष नदारद रहा और अब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के शासनकाल में भी प्रतिपक्ष नहीं है यही नहीं यदि हम अब तक हमारे देश का इतिहास देखें तो आजादी के 22 साल बाद हमारे देश में विपक्ष नजर आया था जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त था अर्थात पंडित नेहरू के 15 साल 206 दिन के शासनकाल में प्रतिपक्ष अस्तित्व में नहीं रहाद्य यही नहीं पंडित नेहरू के बाद प्रधानमंत्री रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में भी कोई अधिकृत प्रतिपक्ष नहीं रहा इंदिरा जी ने देश पर 16 साल से भी अधिक राज किया जिसमें सिर्फ 1969 मैं एक अवसर ऐसा आया जब लोकसभा को पहली बार राम सुभाग सिंह के रूप में विपक्ष का पहला नेता मिला। इंदिरा जी के बाद 10 साल चार माह राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे इन्हें भी प्रतिपक्ष के नेता का सामना नहीं करना पड़ा उस समय भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 1984 में केवल दो ही सीटें मिल पाई थी इसके बाद डॉ मनमोहन सिंह के कार्यकाल में प्रतिपक्ष अवश्य अस्तित्व में रहा किन्तु मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो 19 मई 2014 से प्रधानमंत्री पद पर विराजित है इन के अब तक 8 साल 7 माह के कार्यकाल में भी किसी मान्यता प्राप्त नेता प्रतिपक्ष के अब तक दर्शन नहीं हुएद्य अर्थात आजादी के बाद से अब तक अधिकांश समय आजादी का सिक्का एक तरफ से कोरा या सपाट ही रहा सिक्के पर सरकार ही रही।

अब यदि हम आजादी के बाद के प्रतिपक्ष से सुसज्जित शेष 27 सालों की बात करें तो इस अवधि में हमारे देश में ऐसे प्रतिपक्ष नेता रहे जिन्होंने पूरे विश्व को यह दिखा दिया कि प्रतिपक्ष की भूमिका व उसे निभाने वाला कैसा होता है? इससे पहले हम यह बता दें कि लोकसभा या संसद में मान्यता प्राप्त प्रति पक्ष दल व उसका नेता वही होता है जिस दल को लोकसभा की कुल सीटों का 10 हिस्सा प्राप्त हो अर्थात हमारी लोकसभा की 543 सीटों में से कम से कम 54 या 55 सीटें प्रतिपक्ष के दावेदार दल को मिले। अब यदि यह प्रतिपक्ष नेता की बात करें तो सबकी निगाहें केवल और केवल श्री अटल बिहारी वाजपेई पर जाकर ठहरती है जिन्होंने एक बेजोड़ प्रतिपक्ष नेता की भूमिका का निर्वहन किया। 1993 से 1997 के बीच करीब 4 साल तक प्रतिपक्ष के नेता रहे वे अपनी बेबाक हाजिर जवाबी वह वाकपटुता के लिए जाने जाते रहे। इसलिए वे पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में सम्मान अर्जित करते रहे। अटल जी का प्रधानमंत्रित्व कॉल भी बेबाक रहा। अटल जी के बाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी भी प्रतिपक्ष की नेता रही वह 31 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक प्रतिपक्ष की नेत्री रही लेकिन हमारा अब तक का संसदीय इतिहास गवाह है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी सबसे लंबे समय तक प्रतिपक्ष के नेता रहे। आडवाणी जी 3 चरणों में 7 साल 25 दिन नेता प्रतिपक्ष रहे। तेज तर्रार भाजपा नेत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी 21 दिसंबर 2009 से 26 मई 2014 तक नेता प्रतिपक्ष रही।

हमारे संविधान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का महत्वपूर्ण पद माना जाता है अटल जी आडवाणी जी राजीव जी सोनिया जी शरद पवार जी जगजीवन राम जी और सुषमा स्वराज जी ने अब तक का इस अति महत्वपूर्ण पद पर रहकर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन किया।

इस प्रकार यदि यह कहा जाए कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में इन नेताओं ने अति महत्वपूर्ण योगदान दिया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी पिछले करीब साढे 8 सालों से कांग्रेस इस भूमिका का निर्वहन कर रही है बिना किसी अधिकृत प्रतिपक्ष की नेता के। यही लोकतंत्र की दुहाई है।

कारगर जैव विविधता तंत्र से बचेगी दुनिया

देविंदर शर्मा

कनाडा के मॉन्ट्रियल में संपन्न हुई 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप-15) अधिवेशन में नई राह खोलने वाला जैव-विविधता रूपरेखा प्रस्ताव पारित हुआ है। करीब चार साल तक चली सहमति प्रक्रिया के बाद यह समझौता तैयार हुआ है। इसके तहत वर्ष 2030 तक 23 वैश्विक ध्येयों की प्राप्ति करने का संकल्प लिया गया हैद्द यह नजरिया वर्ष 2050 आने तक दुनिया को अपने तौर-तरीकों को कुदरत के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए तैयार करेगा।

नव-निर्मित रूपरेखा का उद्देश्य जैव-विविधता में हो रहे ह्रास को रोकना और पुनर्निर्माण करना है। आज विश्व बहुत नाजुक पर्यावरण चरण से गुजर रहा है, परिणामस्वरूप धरती पर प्राणी-जीवन छठवीं बार विलुप्त होने की नौबत बनने लगी है। बहुत बड़ी मात्रा में हुआ जैव-विविधता का ह्रास, जिसको अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने 'जैविक प्रलय' का नाम दिया है, एक मानव-निर्मित संकट है और इससे अगले कुछ दशकों में 10 लाख से अधिक प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है।

इस बारे में जैव विविधता रूपरेखा समझौता मील का पत्थर हो सकता है, इस महत्वाकांक्षी ध्येय की प्राप्ति हेतु समयबद्ध सीमारेखा तय की गई है और इससे पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि को नाथने वाले प्रयासों को भी बल मिलेगा। निःसंदेह, जैव-विविधता और पर्यावरण बदलाव का आपस में गहरा रिश्ता है। लगातार बिगड़ते जा रहे मौसमीय संकट को बतौर मददगार एक फलती-फूलती जैव-विविधता की सख्त जरूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि इस ऐतिहासिक जैव-विविधता संधि को 'पेरिस पैक्ट' के विस्तार की तरह देखना ज्यादा मुनासिब होगाद्द मॉट्रियल रूपरेखा और पेरिस संधि, दोनों का कदमताल।

वैश्विक जैव-विविधता रूपरेखा में जिस किस्म का रूपांतर उकेरा गया है, उसके मुताबिक 2030 तक पृथ्वी के कुल भू-भाग का जितना नुकसान पिछले कई दशकों में हुआ है, उसके 30 फीसदी भाग का पुनर्निर्माण करना है क्योंकि फिलहाल महज 17 प्रतिशत ही सही बचा है, इसी तरह बुरी तरह प्रदूषित हो चुके महासागरों की पर्यावरणीय सुरक्षा में 30 प्रतिशत हिस्सा यकीनी बनाना है। इसके लिए फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा करने वाली सब्सिडी व्यवस्था में 500 बिलियन डॉलर की सालाना कटौती की जानी है। साथ ही 2030 तक कीटनाशकों के इस्तेमाल में 50 प्रतिशत की कमी लानी है। इससे किसी क्षेत्र में 'दूसरे ग्रह से आए जैसे लगने वाले बाहरी कीटों' की आमद आधी हो सकेगी, यह होने का एक फायदा टिकाऊ विकास का खाका खींचा जाना भी है। नई संधि में जनजातीय लोगों और वन-वासियों के अधिकारों को यथावत? बनाए रखने की बात भी है।

मॉन्ट्रियल रूपरेखा को साकार करने में हर साल सरकारें, निजी क्षेत्र और भलाई संस्थानों के वित्तीय सहयोग से 200 बिलियन डॉलर का आर्थिक सहायता फंड बनाया जाएगा। एक सघन निगरानी तंत्र भी अपनी जगह बैठाया गया है ताकि धन का इस्तेमाल उचित ढंग से होना सुनिश्चित रहे और ठीक इसी समय सदस्य देशों पर कड़ी निगरानी रहेगी कि वे रूपरेखा के प्रावधानों पर सही अमल कर रहे हैं या नहीं।

कुनिंमग-मॉन्ट्रियल जैव-विविधता रूपरेखा और 2010 में उल्लेखित आइची जैव विविधता ध्येय (जो अधिकांशतः अनजान रहा) में सबसे बड़ा फर्क यह है कि नए तंत्र में निगरानी व्यवस्था शामिल की गई है। हालांकि ध्येय वैश्विक हैं किंतु ध्येय प्राप्ति को मूर्त रूप देना विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अपने राष्ट्रीय हित में होगा। हालांकि बात जब 2030 तक कीटनाशकों का इस्तेमाल आधा करने की आई तो ब्राज़ील, अर्जेंटाइना और भारत असहज हो उठे, लेकिन उम्मीद है कि सार्वजनिक दबाव नीति नियंताओं को संधि के सिद्धांतों के अनुरूप रूपांतर करके नीतियों को व्यावहारिक बनाने को मजबूर करेगा।

औद्योगिकीकृत-कृषि व्यवस्था दुनियाभर के वन-क्षेत्र में तबाही की 80 प्रतिशत जिम्मेवार है, जिसकी वजह से भू-स्रोतों का 52 प्रतिशत हिस्सा बदतर होता गया। इससे खतरे में पड़ी 28000 प्रजातियों में 86 फीसदी के विलुप्त होने की नौबत आ गई है। इस ह्रास की क्षतिपूर्ति खाद्य व्यवस्था का स्वरूप बदले बिना संभव नहीं है। हालांकि बढ़ता डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रॉबोटिक्स और स्वचालित प्रणाली जिस तेजी से लाई जा रही है, उससे औद्योगिकीकृत खाद्य मूल्य शृंखला आगे और बलवान होगी। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एजेंसियां समय-समय पर खतरे की घंटी बजाते आए हैं, नई जैव-विविधता रूपरेखा सदस्य देशों के लिए अपनी कृषि-नीतियों के पुनर्निर्माण में सहायक होगी। लेकिन यह करना उतना आसान है नहीं, जितना लग रहा है। कृषि-आधारित-व्यापार वाले उद्योगपतियों की लॉबी इतनी ताकतवर है कि इस किस्म के प्रयासों को सिरे चढ़ने ही न दे। उदाहरणार्थ सब्सिडी व्यवस्था घटाने का अर्थ होगा- कृषि के बड़े औद्योगिक घरानों के प्रभुत्व का लगातार सिमटना, क्या वे ऐसा होने देंगे? जबकि इनकी करतूतो से ही मिट्टी और पर्यावरण का इतना ज्यादा नुकसान हुआ है।

हालांकि, अब खाद्य व्यवस्था का रूपांतर मित्र खेती की ओर होने के काफी प्रमाण हैं, फिर भी, प्रकृति आधारित हल की राहद्द जो जैव विविधता बचाए और ह्रास की क्षतिपूर्ति भी करेद्द इसमें काफी रुकावटें आएंगी। जहां यूरोपियन यूनियन ने साझा कृषि नीति (कैप) के तहत वर्ष 2023 से टिकाऊ और लचीली कृषि लिए 249 बिलियन यूरो की मदद देने की घोषणा की है वहीं कृषि-व्यापार के धंधेबाजों ने अभी से डर का माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि इससे खाद्य सुरक्षा संकट बनेगा। क्या यूरोपियन संघ उत्पादन के लिए आंकड़ों वाले ध्येय से रहित होकर कीटनाशकों का इस्तेमाल 2030 तक आधा कर पाएगा?

भारत में, पिछले अनुभव बताते दर्शाते हैं कि खतरनाक कीटनाशकों से निजात पाना कितना मुश्किल है, इसका एक बढ़िया नमूना केरल के कासलगंज जिले में काजू की खेती करने वालों के जीवन के लिए काफी नुकसानदायक सिद्ध हुए एंडोसल्फान नामक कीटनाशक का इस्तेमाल और दुरुपयोग तजने का है। जैव-विविधता रूपरेखा द्वारा कीटनाशकों का इस्तेमाल 50 फीसदी घटाने का ध्येय इसलिए भारत के बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ऐसे हर प्रयास को पग-पग पर ताकतवर लॉबी की डाली अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही, पर्यावरण तंत्र का 30 फीसदी पुनर्निर्माण करने वाले ध्येय का टकराव भी औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचा विकास नीतियों के साथ होगा। छत्तीसगढ़ के हसदेओ अरंद कोयला खान वाले मामले में, जहां पर जनजातीय समुदायों ने खनन के खिलाफ लंबे समय तक आंदोलन चलाया था, तब भारत के वन्यजीवन संस्थान द्वारा करवाया जैव-विविधता सर्वेक्षण अपने-आप में आंखें खोलने वाला है। जैव-विविधता के खजाने से भरपूर इलाकों में पर्यावरण के बचाव को सर्वोपरि तरजीह होनी चाहिए। इसी प्रकार, जैव-विविधता से परिपूर्ण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जहां पर विशालकाय सामरिक परियोजना के लिए 8 लाख पेड़ काटने की योजना है, जबकि इस इलाके में दो राष्ट्रीय वन्य क्षेत्र और बायोस्फियर रिजर्व पार्क हैं। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए हरियाणा और मध्यप्रदेश में पेड़ लगाने के औचित्य पर पर्यावरणविद? सवाल उठा रहे हैं।

बहरहाल, वैश्विक जैव-विविधता रूपरेखा द्वारा पेश चुनौती, जिस दुनिया में हम रहते हैं उसकी पुनर्कल्पना करने में दूरगामी होगी और ठीक इसी समय आर्थिक नीतियों की सोच और रुख की लीक सुधारने में भी। पर्यावरण रक्षा सुनिश्चित किए बिना अर्थव्यवस्था किस काम की।

एलन मस्क की ठसक, मूर्खों का रश्क

जनाब एलन मस्क, पढ़ा कि तुम्हें ट्विटर के वास्ते एक मूर्ख बंदे की तलाश है! मैं हूं न! मुझसे बड़ा और परमानेंट मूर्ख तुम्हें पूरी दुनिया में खोजे नहीं मिलेगा। मेरी मूर्खता के चर्चे मेरे शहर से लेकर दुनिया के कोने-कोने में हैं।

मैं अभी से नहीं बचपन से ही मूर्ख हूं। मेरी पढ़ाई-लिखाई, नौकरी और शादी मूर्खता के मापदंडों के आधार पर ही हुई। अपनी मूर्खता को मैंने कभी छिपाने की कोशिश नहीं की। छिपाता भी क्यों? मूर्ख होना व कहलवाना मेरे वास्ते उपलब्धि जैसा है। लेकिन लोग ऐसा नहीं समझते। वे ऐसा क्यों नहीं समझते, यह समझने की कभी मैंने कोशिश नहीं की। मगर तुम समझोगे, मेरे लिए यही काफी होगा।

कभी मौका मिले तो तुम बरेली आना। बरेली में एक पागलखाना है। उस पागलखाने का मैं बरसों पुराना सदस्य हूं। मेरे नाम की सीट वहां हर वक्त बुक रहती है। पागलखाने का हर एक बंदा मुझे बहुत अच्छे से जानता है। पता है, मुझे सबसे अधिक शांति यहीं आकर मिलती है। यहां हर पागल एक-दूसरे को समझता है। दु:ख-सुख में साथ खड़ा होता है। कभी न किसी की जाति पर बहस करता है न राजनीति पर न नेता पर न समाज पर न साहित्य पर न व्यवस्था पर। यहां सबकी अपनी-अपनी बतकही है।

मूर्खता का यही एक परम सुख है कि दुनिया बेशक मुझको मूर्ख समझती रहे किंतु मैं उन्हें खुद से बड़ा मूर्ख मानता हूं। जरा-बहुत मूर्खता हम सभी में है मगर हम स्वीकार करने से डरते हैं।

तुम्हारा चुनाव कतई ठीक है। ट्विटर ही नहीं सोशल मीडिया का हर मंच मूर्खों के सुपुर्द कर देना चाहिए। समझदारों को हम देख ही चुके हैं। देख रहे हैं। कि, कैसे वे इस मंच से निरंतर नफरत और फेक न्यूज का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। हर आदमी यहां ट्रोल बना किसी न किसी की टांग खींचे में लगा है। समझदार भी कित्ते नासमझ होते हैं! यह बात मुझे यहीं आकर मालूम हुई।

पता है एलन, हम जैसे चंद मूर्खों ने ही इस दुनिया को अब तलक बचाए रखा है। हालांकि हमारी मूर्खता पर लोग हंसते हैं, हमें ताने देते हैं, हमें बुरा-भला कहते हैं फिर भी हम बुरा नहीं मानते। बुरा मानकर कर भी क्या लेंगे! ये दुनिया खुद ही इत्ती बड़ी मूर्ख है, इसका अहसास ही नहीं इसे। समय और तकनीक जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है दुनिया में मूर्खता का ग्राफ और बढ़ता ही चला जा रहा है। मुझे हर कथित समझदार चेहरे के पीछे एक मूर्ख का चेहरा नजर आता है। लेकिन, ऐसा मानेगा कौन? बहरहाल, मुझे अपने मूर्ख होने पर शक कतई नहीं। ट्विटर को मैं बहुत अच्छे से संभाल सकता हूं। बस एक दफा तुम मेरी मूर्खता को आजमा कर देख लो।

लेखक:- अंशुमाली रस्तोगी

राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए लगा रहे ऐड़ी चोटी का जोर

कौन होगा 2023 में विधायक, कर्जमाफी के हेर-फेर में उलझे किसान

माही की गूंज, मंदसौर। साहिल अगवान

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। एमपी में 7 दिसंबर 2023 को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। राज्य में जहां एक तरफ भाजपा पूरे जोर-शोर के साथ कार्यक्रमों और योजनाओं का ऐलान कर रही है और सीएम शिवराज सिंह चौहान दिन-रात मेहनत कर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस अभी से उम्मीदवारों पर विचार कर रही है। प्रदेश में मिली हुई सत्ता जाने के बाद इस बार कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए। पार्टी ने उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए भी फॉर्मूला बना दिया है।

ज्यादातर सिटिंग एमएलए को टिकट

मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में इस समय कांग्रेस के 96 विधायक हैं, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा के पास 126 विधायक हैं। 4 निर्दलीय विधायक हैं, जबकि दो बसपा और एक सपा का विधायक है। खबर है कि, कांग्रेस इस बार एमपी में करीब 80 वर्तमान विधायकों को टिकट दे सकती है, जबकि 20 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं।

अगर बात करे मंदसौर की तो जिले की किसी भी विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा नही हे। भाजपा वापस अपना कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में हे। सर्वे में हर रहे विधायको की जगह नया चेहरा उतरने का प्लान तैयार कर रही है। चुनावी समर को लेकर विभिन्न राजनीतिक पाटियों से जुड़े नेता अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं। इनमें कुछ दावेदार ऐसे भी है जो पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं या इस वर्ष प्रथम बार दावेदारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी है जो पार्टी हाईकमान के सम्मुख दोबारा अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि इनकी दावेदारी इनके कार्यकाल और कार्यों के आधार पर तय होना है। इंडिया की खबर ने गरोठ विधानसभा क्षेत्र से ऐसे संभावित दावेदारों की सूची तैयार की है साथ ही यह जानने का प्रयास भी किया है कि इनकी दावेदारी कितनी मजबूत है।

गरोठ जिला बनाओ सबसे बड़ा मुद्दा

गरोठ को जिला बनाने के लिए दोनों राजनीतिक पार्टियां चुनावी सर्वे में जनता को लगा कर वोट मांगती है। गरोठ जिला बनाओ वोट मांगने का क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है मगर अब तक गरोठ जिला नहीं बन पाया। गरोठ जिला को लेकर क्षेत्र की जनता आवास छोड़ चुकी है।

कर्जमाफी के हेरफेर में उलझे किसान

फिलहाल अगर किसानों की बात करे तो कांग्रेस किसान का 3 लाख तक का कर्जा माफ करने का ऐलान करने की तैयारी में है। कांग्रेस के किसान कर्ज माफी के ऐलान के कारण डिफाल्टर किसान कर्जा नहीं चुका रहे हैं, हालांकि सरकार ऐसे डिफाल्टर किसानों को भी सहूलियत देने में पीछे नहीं है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के राडार पर आए किसान कर्ज माफी के हेरफेर में उलझे हुए हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय किसानों का कर्जा माफ हुआ था। 28 लाख किसान को फायदा हुआ था और अब सरकार में आने पर पुराना वचन निभाने का काम सरकार पूरा करेगी। वहीं प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया का कहना है कि, राज्य सरकार डिफाल्टर किसानों को सभी तरह की सुविधाएं दे रही हैं। किसान अपना कर्जा चुकाते हैं तो उनके ब्याज की राशि भी सरकार भरेगी। सरकार ने किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी हैं डिफाल्टर किसानों को सरकार हर संभव मदद दे रही है और जो किसान डिफाल्टर हुए हैं वह कांग्रेस की देन हैं।

प्राकृतिक और जैविक खेती के विकास विस्तार के लिए कृषकों को दिया प्रशिक्षण

माही की गूंज, खरगोन।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक खेती के विकास विस्तार के लिए झिरन्या के ग्राम मलगांव कोठा में कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. जीएस कुलमी ने कहा कि, रासायनिक पदार्थों के द्वारा उत्पादित अन्न खाने से हमारे शरीर और मन दोनों रोगी होते जा रहे हैं। शुद्ध सात्विक प्राकृतिक तरीके से उगाए गए अनाज एवं फल सब्जियां शरीर और मन दोनों के स्वास्थ्य के लिए उत्तम होते हैं। इसमें कृषि की लागत भी कम होती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है।

वहीं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने प्राकृतिक खेती के अनेक लाभ गिनाते हुए जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत एवं फसल सुरक्षा के लिए जैविक कीटनाशक तैयार करने की विधियां समझाई। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी डॉ. संतोष पाटीदार ने प्राकृतिक खेती का पंजीयन कराने तथा भूमि सुधार एवं आर्थिक स्वावलंबन के लिए सभी किसानों को प्राकृतिक खेती करने की सलाह दी। साथ ही मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना लेने की विधि समझाई।

तकनीकी अधिकारी संतोष पटेल ने उपस्थित किसानों के डाटा संकलन किये। कार्यक्रम के अंत में कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन द्वारा किसानों को जीवामृत एवं घनजीवामृत बनाने के लिए जैविक गुड़ एवं दलहनी आटा आदि सामग्री दी गई। ज्ञातव्य है कि ग्राम मलगांव कोठा में अधिकांश किसान प्राकृतिक खेती करते हैं जिनके जैविक फसल उत्पाद अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं।

कलेक्टर ने किया ईव्हीएम गोडाऊन का किया निरीक्षण

माही की गूंज, शाजापुर।

जिला मुख्यालय पर भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. के निर्देशानुसार ईव्हीएम वेयरहाउस खोलकर त्रैमासिक निरीक्षण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने किया। जिला उप निर्वाचन अधिकारी ने अजीत श्रीवास्तव ने बताया कि, आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए बैंगलूरू से नवीन एम3 मॉडल की मशीन प्राप्त होने के पूर्व रिक्त कक्षों की साफ-सफाई के लिये ईव्हीएम नोडल अधिकारी को पत्र जारी करने के लिए निर्देश प्रदान किए गए। उन्होने बताया कि, कलेक्टर दिनेश जैन ने ईव्हीएम गोडाउन पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक कक्ष में एवं बाहरी परिसर में लगे सीसीटीव्ही कैमरे तथा जिसका डिस्प्ले सुरक्षा कर्मी के कक्ष में स्थापित है। जिसमें 12 सीसीटीव्ही कैमरे स्थापित हैं एवं 1-4 का पुलिस गार्ड तैनात है का निरीक्षण किया गया है वहीं अग्निशमन यंत्र लगे हुए है उनका निरीक्षण किया गया है। इस दौरान जिला निर्वाचन पर्यवेक्षक सुनील तिवारी एवं सहायक प्रोग्रामर पुलिस गार्ड उपस्थित थे।

बस स्टेण्ड पर वर्षों से हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए अंतिम बार दिया 7 दिवस का समय

माही की गूंज, गरोठ।

बस स्टेड पर वर्षो से हो रहे अवैध को अतिक्रमण को राजस्व विभाग के अमले ने हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलीस बल मौके पर मौजूद रहा। गरोठ तहसीलदार नारायण नंदेड़ा ने बताया कि, प्रकरण क्रमांक 0002 अ-70/2020-21 में पारित आदेश दिनांक 10 दिसंबर 2021 के पालन हेतु तहसीलदार गरोठ के आदेश क्रमांक 3012 दिनांक 23 दिसंबर 2022 से गठित दल द्वारा कस्बा गरोठ स्थित भूमि सर्वे नंबर 566/मीन-1 रकबा 0.056 हेक्टेयर भूमि भूमि पर अनावेदकगण शिवराम सिंह पिता ब्रजराज सिंह, राजेन्द्र सिंह, कल्याण सिंह पिता शिवराम सिंह जाति राजपूत निवासी गरोठ का कब्जा हटाकर आवेदक शफी मोहम्मद पिता अब्दुल रहमान जाति पिंजारा निवासी गरोठ को कब्जा प्रदायगी की कार्यवाही के दौरान अनावेदकों द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा स्वीकार किया जाकर कब्जा हटाने हेतु अथवा स्थगन आदेश हेतु 7 दिवस का समय चाहा गया। यह भी उल्लेखनीय है कि, अनावेदकों द्वारा तहसीलदार गरोठ के प्रकरण क्रमांक 0002 अ-70/200-21 में पारित आदेश दिनांक 10-12-21 के विरुद्ध श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गरोठ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अपील स्वयं अनावेदकों द्वारा ही पुनः वापस ले ली। मौके पर तहसीलदार गरोठ द्वारा न्यायहित में अनावेदकों को अंतिम बार 7 दिवस का समय दिया गया।

अनावेदकों द्वारा सात दिवस में सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त न होने की दशा में स्वयं कब्जा हटाया जाने की सहमति एवं स्वीकृति प्रदान की गई।

दुपहियां वाहन पर ले जाया जा रहा 45 किलो डोडाचूरा किया जप्त

एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

माही की गूंज, रतलाम।

नए वर्ष के दूसरे ही दिन रतलाम पुलिस ने दूसरी एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई करते हुए 45 किलो डोडाचूरा बरामद किया है। जावरा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने दुपहिया वाहन से परिवहन कर ले जाए जा रहे 45 किलो डोडाचूरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी जावरा के ही एक व्यक्ति से डोडाचूरा ले जाना बताया। इस पर जावरा के युवक को भी सह आरोपी बनाकर उसके खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी प्रकाश गडरिया ने बताया सूचना मिली थी कि दो युवक बाइक से अवैध रूप से डोडाचूरा ले जाने वाले हैं। इस पर पुलिस ने जावरा उज्जैन रोड पर लालाखेड़ा फंटे के यहां चैकिंग शुरू की। चैकिंग के दौरान एक बाइक क्रमांक एमपी 09 क्यूके 4184 पर एक युवक धाकड़ चौराहे की तरफ से एक बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। उसकी बाइक पर पीछे थैला बंधा हुआ था। चैकिंग के दौरान पुलिस ने उन्हें रोका और तलाशी ली तो उसके पास से बोरे में भरा हुआ डोडाचूरा पाया गया। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी गौतमपुरा इंदौर थाने के अत्याना गांव निवासी 26 वर्षीय अर्जुन पिता नागूलाल गायरी होना पाया गया।

जिले का पहला गिर प्रोजेक्ट शुरू

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले का पहला गिर प्रोजेक्ट सीतामऊ रोड पर गांव गुर्जर बर्डीया में नए वर्ष पर प्रारंभ हुआ। इस प्रोजेक्ट के संबंध में गांव के किसानों का कहना है कि, इस प्रोजेक्ट के द्वारा किसानों को भी फायदा होगा। एक समय था जब गिर गायों को देखने के लिए मंदसौर जिले से बाहर राजस्थान, गुजरात, महू एवं अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता था। वहां पर गिर गाय देखने को मिलती थी। लेकिन अब यह सुविधा गांव गुर्जर बर्डीया में ही प्रारंभ हो गई है। अब किसान को गिर प्रोजेक्ट के बारे में जानना है या गिर गाय को पालना हो। जिसके लिए किसान आसानी से गांव के केंद्र पर जाकर उसके बारे में जानकारी ले सकता है। यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से किसानों की आर्थिक विकास का प्रेरणा स्त्रोत बनेगा। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को शासकीय दर पर ही गिर नस्ल के केड़े प्राप्त होंगे। जिससे किसानों के घर पर जो पशु हैं, उसमें नस्ल सुधार होगा। जब नस्ल सुधार होगा। उससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा और दूध के उत्पादन के बढ़ने से किसान आर्थिक रूप से सशक्त होगा।

पशुपालन विभाग के उपसंचालक डॉ मनीष इंगोले का कहना है कि वर्तमान में 25 गिर गायों को उनके बच्चों सहित लाया गया है। यह गाय दूध देने में सबसे अच्छी हैं। इसके साथ ही यह सभी मौसम के अनुकूल ढल जाती है। यह प्राचीन गिर गाय की नस्ल है। इनके रहने के लिए बाड़ों का निर्माण किया गया है। इनका वंश भी बड़ेगा। इसके साथ ही जिले में नस्ल सुधार का कार्य भी होगा। यह क्षेत्र बेहतर गिर गाय नस्ल का क्षेत्र बनेगा। गिर गाय केंद्र को देखकर किसानों के अंदर भी इनको पालने की प्रेरणा जागेगी। जिससे किसान दूध के क्षेत्र में, जैविक कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे।

नए वर्ष के साथ बड़ी ठंड, स्कूल के समय परिवर्तन की उठी मांग

माही की गूंज, मंदसौर। नए वर्ष के साथ ही कड़ाके की ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर दिखने लगा है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मंगलवार शाम होते ही ठंडी हवाओं में रजाई में दुबकने को मजबूर कर दिया। जिले में रात का तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुच गया जबकि दिन का तापमान 22 डिग्री के आसपास रहा। सोमवार का तापमान गिरावट के साथ न्यूनतम 8.4 और अधिकतम 19.7 रहने का अनुमान है। मंगलवार को दिन भर सर्द मौसम रहा लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए वहीं बुधवार को भी इससे राहत नही मिलने मिली। उधर मौसम विभाग ने जिले में घने कोहरे के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के साथ ही जिला भी शीत लहर की चपेट में है। तापमान में गिरावट का दौरा जारी है। लोग सोशल मीडिया पर प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों के समय में परिवर्तन की मांग कर रहे है। कड़ाके की ठंड के चलते प्रदेश के कई जिलों में छुट्टियां घोषित होने की खबर के बाद जिले में भी स्कूलों में छुट्टियों की मांग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जा रही है। हालांकि बुधवार सुबह तक स्कूलों के समय परिवर्तन या छुट्टियों को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया।

जलवायु सुधार दिवस, कलेक्टर ने की बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनने की अपील

माही की गूंज, शाजापुर। देश में एनर्जी स्वराज फाउण्डेशन द्वारा जलवायु सुधार दिवस (सीसीडी) के रूप में 4 जनवरी को मनाया जा रहा है। जिले के सभी नागरिक सहित समस्त शासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारीयों से भाग लेने के साथ इस 4 जनवरी के दिन बिना इस्त्री (प्रेस) किए हुए कपड़े पहनकर 200 ग्राम कार्बन डाई ऑक्साईड के उत्सर्जन को रोकने में सहभागी बनने और जलवायु सुधार दिवस पर इस्त्री (प्रेस) का उपयोग नहीं करने की अपील कलेक्टर दिनेश जैन ने की है। कलेक्टर ने जलवायु सुधार की शपथ लेते हुए कहा कि, मैं 4 जनवरी को एनर्जी स्वराज फाउंडेशन की जलवायु सुधार (सीसीडी) के लिए चुनौती लेते हुए मैं 4 जनवरी को बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने जा रहा हूं और 200 ग्राम कार्बन डाई ऑक्साईड के उत्सर्जन को बचाऊंगा। मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि वे भी जलवायु सुधार के लिए आगे आएं और शपथ ग्रहण करते हुए सहभागी बने एवं अन्य नागरिकों को भी इसमें भाग लेने के लिए प्रोस्ताहित करता हूँ। साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों से कहा कि वे शपथ लेते हुए वीडियो एवं फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया हेण्डल पर हेश टैग सीसीडीचेलैंज के साथ साझा कर सकते हैं। राज्य शासन द्वारा चलाए गए ऊर्जा साक्षरता अभियान में शुरूआत से ही अग्रणी रहते हुए शाजापुर जिले ने निरंतर कार्य करते हुए जनता को इसके प्रति जागरूक किया है। इस अभियान में जिले से एक लाख से अधिक नागरिकों ने हिस्सा लेकर पंजीकरण कराया है और 30 हजार से अधिक लोगों ने प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं।

80 लाख की चोरी के सामान के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

माही की गूंज, शाजापुर।

जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं पतारसी के लिए एसपी जगदीश डावर ने सभी राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारीयों को निर्देशित किया है। पुलिस ने स्थानीय सीसीटीवी कंन्ट्रोल रूम पर एसपी जगदीश डावर ने आरोपी से संदिग्ध अवस्था में करीबन 80 लाख रुपये की अवैध शराब, पेट्रोल दृ डीजल व अन्य संदिग्ध सामान बरामद किये जाने के मामले में खुलासा किया है। इस दौरान एएसपी टीएस बघेल व एसडीओपी बेरछा भविष्य भास्कर, एसडीओपी श्रीमती दीपा डोड़वे भी मौजूद रही।

एसपी जगदीश डाबर ने बताया कि, थाना प्रभारी सुंदरसी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि थाना सुंदरसी के ग्राम झण्डाखेडा में शराब एवं चोरी से संबंधित वस्तुओ एवं पेट्रोल डीजल गैस टंकी आदि का अवैध कारोबार किया जा रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एएसपी के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी बेरछा के नेतृत्व में थाना सलसलाई, सुंदरसी, बेरछा, अकोदिया व शुजालपुर मंडी के प्रभारीगणो की टीमें गठित की गई और बड़ी मात्रा में शराब एवं चोरी से संबंधित वस्तुओ एवं पेट्रोल डीजल गैस टंकी अवैध कारोबार के विरूद्ध कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एसपी डावर ने बताया कि, ग्राम झण्डाखेडा निवासी दुर्गा पुरी गोस्वामी अपने घर के अंदर अवैध शराब रखे हुए था। पुलिस ने तलाशी की तो उसके घर से तलाशी के दौरान कुल 24 संदिग्ध मोटर सायकिल, एक महिंद्रा पीकअप एमपी 09 जीएफ़ 3992 व एक छोटा हाथी बिना नम्बर, 6 ट्रेक्टर बिना नम्बर के, एक कमांडर जीप, 27 टच मोबाइल, 32 किपेड़ मोबाइल, 6 टीवी 12 हेंड वेयर वॉल फेन, एक एक्जास फेन, दो छोटे गैस चूल्हे, एक बड़ा गैस चुला, 5 एक्जास फेन की पंखड़ी, 110 ब्रेक शुज, रेलोक्स कंपनी के एलईडी बल्ब, 13 रिसीवर, मोटर सायकल के 10 सफ़ेद मडगार्ड, बड़े वाहन के 13 ट्यूब कीमती, मोटर सायकल के 25 ट्यूब, मोटर सायकल के 52 ट्यूब, माचो कंपनी अडर वियर, लक्स कंपनी के अंडर वियर कीमती, आरपार कंपनी की जुत्ते, बैराठी कंपनी की चपल, स्टार गोल्ड कंपनी के बल्ब, बजाज कंपनी का छत पंखा, स्पेशल बीड़ी के दो कार्टून , साउंड मशीन, मोटर सायकल के टायर, सर्वो कंपनी के ऑइल के 15 डिब्बे, गोल्ड कंपनी के ऑइल के 20 डिब्बे, सर्वो कंपनी के आईल के 17 डिब्बे, हुक्स कंपनी के 2 कटर, पेट्रोल 220 लीटर कीमती 23 हजार 980 रुपए, डीजल 180 लीटर कीमती 16 हजार 920 रुपए, गैस टंकी 10 मिले जिसकी जुमला किमत करबीन 80 लाख रुपये होना पाया गया। आरोपी दुर्गापुरी से घर से मिले सामान के बिल एवं व्यापार करने के लाईसेन्स के बारे में पुछने पर उसके द्वारा कोई बिल, लाईसेन्स या अन्य कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

एसपी डावर ने बताया कि, आरोपी दुर्गापुरी के विरूध्द थाना सुन्दरसी में अपराध क्र 02/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट व अपराध क्र 03/23 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का दर्ज कर विवेचना में लिया गया। उन्होंने बताया कि, उक्त कार्य में थाना प्रभारी सुन्दरसी निरीक्षक रतनलाल परमार, थाना प्रभारी शुजालपुर मण्डी संतोष वाघेला, बेरछा थाना प्रभारी इनिम टोप्पो, अकोदिया थाना प्रभारी अरविन्द तोमर तथा थाना सुन्दरसी के सउनि पी एस तोमर व आरक्षकगण मनोज शर्मा 258, वसीम एहमद 171, ओम प्रकाश 604 व मआर आदित्या जाट 370 की मुख्य भूमिका रही, जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।

प्रवासी भारतीय दिवस के लिए महेश्वर होगा तैयार

माही की गूंज, खरगोन।

17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन इंदौर में होगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन को लेकर मप्र शासन इसे एक अवसर के समान देख रहा है। इस दौरान इंदौर व आसपास के पर्यटन स्थलों पर भी प्रवासी भारतीय आ सकते हैं। इसके लिए नर्मदा रिट्रीट में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एक बैठक ली। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने वाले मेहमानों के महेश्वर पहुंचने को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कलेक्टर ने कहा कि, नगर में व्यवस्थित रूप से साफ सफाई एवं यातायात सुचारू रूप से संचालित हो इस ओर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा नगर में फैसिलिटेट सेंटर और हेल्पडेस्क सेंटर भी बनाना है।

इसके लिए कलेक्टर कुमार ने कहा कि, नर्मदा घाट क्षेत्र और किला एवं अन्य धरोहर को देखने कुछ मेहमान प्रवासी भारतीय सम्मेलन से यहां पहुंच सकते हैं। जिसे देखते हुए नगर में स्वागत द्वार एवं नर्मदा घाट क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से शौचालय व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए। वही गाइड की व्यवस्था के अलावा महेश्वर पर्यटन पर आधारित किताब जिसमें समस्त जानकारी उपलब्ध हो ऐसी व्यवस्था करना है। मेहमानों के लिए आने-जाने का मार्ग व्यवस्थित हो ऐसी सुविधाएं भी करना जरूरी है। नगर के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य जनों ने अपने सुझाव में कहा कि लाइट एंड साउंड सिस्टम निमाड़ उत्सव स्वागत द्वार जैसे कार्य होना बहुत जरूरी है जिसे देखते हुए कलेक्टर ने कहा कि शीघ्र ही इस दिशा में काम पूर्ण होंगे।

बैठक में एसपी धर्मवीरसिंह, एसडीएम अग्रिम कुमार एसडीओपी मनोहर सिंह गवली थाना प्रभारी पंकज तिवारी नगर परिषद सीएमओ मनोज शर्मा के अलावा नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि गजराज यादव, नगर व्यापारी संघ अध्यक्ष बल्लभ सराफ भूपेंद्र जैन दामोदरदास महाजन के अलावा अन्य पार्षद व उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे।

लाइजीनिंग अधिकारी होंगे नियुक्त

17वें भारतीय दिवस का आयोजन 8 से 10 जनवरी को और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन 11 से 12 जनवरी को इंदौर में होना है। इस दौरान आने वाले अतिथियों के सतकार में जिले के कई अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। इसमें महेश्वर, बड़वाह डिवीजन के कई अधिकारी शामिल होंगे। इस कार्य के लिए 38 अधिकारियों को सूचीबद्ध किया गया है।

देश का राष्ट्रीय खेल क्या है...? भाजपा सांसद बोले- कबड्डी, क्रिकेट

माही की गूंज, खण्डवा।

जब भाजपा के एक सांसद से पूछा गया कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? तब इसका जो जवाब उन्होंने दिया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। खंडवा से भाजपा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पत्रकारों को सीधे तौर से यह नहीं बता सके कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि, इस बातचीत के दौरान भाजपा सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि वो अपने क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करें और इसी के तहत वो यहां आए थे। लेकिन उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है।

सांसद खेल महोत्सव के दौरान खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से जब पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो उन्होंने कबड्डी को राष्ट्रीय खेल बता दिया। जब उनके बगल में खड़े भाजपा नेता ने उन्हें कान में हॉकी राष्ट्रीय खेल बताया, तो उन्होंने कहा कि पहले कभी आपकी भी हॉकी राष्ट्रीय खेल हुआ करता था। लेकिन अब कबड्डी और क्रिकेट जैसे खेल प्रमुख हैं।

राष्ट्रीय खेल से संबंधित पूछे गये सवाल के जवाब में भाजपा सांसद ने कहा कि, राष्ट्रीय खेल तो हमारा, कबड्डी को पहले प्राथमिकता देते थे... लेकिन आज कबड्डी को पीछे छोड़ते हुए, क्रिकेट ने उसका स्थान ले लिया है। पास में खड़े भाजपा नेता के बोलने पर सांसद ने फिर कहा कि हॉकी भी कभी हमारा राष्ट्रीय खेल हुआ करता था। लेकिन आज धीरे-धीरे कबड्डी को कम लोग सराहते हैं, हॉकी को बहुत कम लोग सराहते हैं लेकिन इस तरह का आयोजन करने का आदेश हमारे प्रधानमंत्री का है।

जनसहयोग से 325 जनजातीय विद्यार्थियों को मिले ट्रेक शुट और जूते

माही की गूंज, खरगोन।

बड़वाह सीएम राइज स्कूल के हॉल में जनभागीदारी से एक साथ 325 बालक बालिकाओं को ट्रैक शुट और जूते प्रदान किये गए। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम निर्देशानुसार बड़वाह एसडीएम बीएस कलेश ने नगर के व्यापारी और समाज सेवा से जुड़े नागरिकों के सहयोग से यह सामग्री प्रदान की गई।

इस अवसर पर कलेक्टर कुमार ने विद्यार्थियों से कहा कि, जनसहयोग से प्रदान की गई सामग्री कोई दान नहीं है। यह समाज की विद्यार्थियों के प्रति कृतज्ञता है। यह समाज की जिम्मेदारी भी है कि अपने छात्रों को एक अच्छा माहौल और अवसर प्रदान करें। शिक्षा के माध्यम से परिवार और समाज का नाम रोशन किया जा सकता है। आप लोगों से पहले कई लोगो ने ऐसा करके दिखाया है। अब अवसर आपके पास है। आप स्वस्थ रहे और खूब पढ़ो। इस कार्यक्रम के माध्यम से बड़वाह नगर के 7 जनजातीय विभाग के छात्रवासों के 75 बालको और 250 बालिकाओं को ट्रैक शुट व जूते प्रदान किये गए। ज्ञात हो कि कलेक्टर श्री कुमार के प्रयासों से जिले की सभी जनजातीय छात्रावासों के बालक-बालिकाओं को जन सहयोग से ट्रेकशुट व जूते प्रदान करने की शुरूआत की है। अब तक भीकनगांव के दौड़वा व अन्य छात्रावासों सहित पिपलझोपा के छात्रावासों में यह सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इस मौके पर एसडीएम बीएस कलेश, जिला शिक्षा अधिकारी हेमेंद्र वडनेरकर, तहसीलदार श्रीमती रंजना पाटीदार, जनपद सीईओ रोहित पचौरी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

एक माह में बनकर तैयार होगा 50 सीटर छात्रावास

बड़वाह में महाविद्यालय की छात्राओं के लिए नवीन निर्माणधीन छात्रावास का भी कलेक्टर कुमार ने अवलोकन किया। पीआईयू की एसडीओ आरती पटेल ने बताया कि 2 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से बन रहे महाविद्यालयीन बालिका छात्रावास 1 माह में बनकर तैयार होगा।

एसडीओपी और टीआई ने शहर के गुंडों की थाने में लगाई क्लास

निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने की दिलवाई शपथ

माही की गूंज, बड़वानी।

आगामी नगर पालिका चुनाव को देखते हुए एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र निगरानी एवं गुंडा बदमाशों की थाना पर परेड कराकर, वर्तमान में वह क्या काम कर रहे हैं इसको चेक करने के निर्देश दिए है। एसपी दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन के पालन में टीआई राजेश यादव ने कार्य करते हुए आज थाना क्षेत्र के 22 गुंडा बदमाशों को थाने पर हाजिर कराया और हाजिर करा कर प्रत्येक गुंडा बदमाश वर्तमान में क्या काम कर रहा है उसकी जानकारी ली एवं साथ ही उनके अपराधिक रिकार्ड का अपडेट भी लिया गया। गुंडों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा एट्रोसिटी जैसे कई अपराध दर्ज होना पाए गए हैं। इन सभी को हिदायत दी गई कि वर्तमान नगर पालिका चुनाव में यदि शांति भंग करने की कोशिश की तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी एवं सभी गुंडों को नगर पालिका चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं चुनाव को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने की शपथ भी दिलवाई गई।

गुंडों की परेड के दौरान एसडीओपी कमल सिंह चैहान, टीआई राजेश यादव सहित स्टाफ उपस्थित रहा। टी आई राजेश यादव ने बताया कि, नगर पालिका चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए समय-समय पर गुंडे बदमाश एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई धारा 107, 116, धारा 110 सीआरपीसी एवं जिला बदर , एनएसए की कार्रवाई जारी रहेगी।

जिला पंचायत सीईओ ने ऑपरेशन सत्यापन के तहत किया निरीक्षण

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले के नवाचार आपरेशन सत्यापन के तहत जिला पंचायत सीईओ अनिल कुमार डामोर ने ग्राम जलगोन में आगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय और मिडिल स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होने आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर पोष्टिक आहार से जुड़ी जानकारी लेकर रिकार्ड के रख रखाव हेतु निर्देश दिए। उत्कृष्ट प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर बच्चो से जोड़ घटाव और गिनती पूछी। बच्चो को जोड़ नहीं आने पर उन्होंने शिक्षक को निर्देशित किया कि बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये एवं बच्चों के शिक्ष के स्तर को बढ़ाया जाये। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक नियमित रूप से शाला आये एवं बच्चों को पढ़ाये साथ ही खेल-खेल में गतिविधियों का आयोजन कर बच्चों को सीखाये। ग्राम के शासकीय हाई स्कूल में उपस्थित शिक्षक से बच्चो की अटेंडेंस और शिक्षको की अटेंडेंस की जानकारी लेकर अध्यापन कार्य का निरीक्षण किया और मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता देखी गई। साथ ही भोजन बनाने वालो को भोजन बनाने के दौरान हरी सब्जियों को शामिल करने हेतु कहा गया। विद्यालय परिसर में स्वच्छता को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सचिव और संबंधित कर्मचारियों को शीघ्र परिसर में स्वच्छता कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पानसेमल जनपद पंचायत सीईओ महेश पाटीदार, पानसेमल विकास खंड शिक्षा अधिकारी अरुण मिश्रा, विकास खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ अरविंद किराडे, विद्युत विभाग के कनिष्ठ यंत्री शिव प्रसाद पेंड्राम, परियोजना अधिकारी कनेल सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

अवैध देशी-विदेशी मदिरा जप्त कर दर्ज किए 5 प्रकरण

माही की गूंज, धार।

जिले में आबकारी विभाग द्वारा पंचायत चुनाव के मद्देनजर चलाये जा रहे विशेष अभियान में क्षेत्र में अवैध देशी विदेशी मदिरा जप्त कर 5 प्रकरण दर्ज किये गए। सहायक आबकारी आयुक्त श्री विक्रम दीपसांगर के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान में आबकारी विभाग के द्वारा बुधवार को कार्यवाही कर सरदारपुर वृत क्षेत्र मे विधिवत दबिश दी गई। जिसमें अवैध शराब जप्त की कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के 5 प्रकरण दर्ज किये।

उपलब्ध संसाधनों से बेहतर सुविधाएं देने के प्रयास

माही की गूंज, खरगोन।

बड़वाह सिविल अस्पताल की स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए बुधवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बैठक की। यहाँ मौजूद जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल परिसर में प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होने की स्थिति में जरूरतमंदों को निजी डॉक्टरों से प्लास्टर चढ़वाना, दांत के डॉक्टर होने के बावजूद सामग्री नहीं होना, दवाइयां नहीं होना व अन्य डॉक्टरों की कमी होने की समस्या कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के समक्ष रखी। कलेक्टर श्री कुमार ने बीएमओ श्री मिमरोट और सीएमएचओ डॉ डीएस चौहान ने इस संबंध में जानकारी ली।

कलेक्टर कुमार ने कहा कि, छोटी-छोटी समस्याएं स्थानीय स्तर पर कलेक्टर से अनुमति लेकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकती है। प्लास्टर के सम्बंध में कलेक्टर ने कहा कि रोगी कल्याण समिति की राशि से खरीदी की जा सकती है। प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करें। बीएमओ को निर्देश दिए कि शासन स्तर से जो सामग्री नहीं मिल रही है उसके प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। बीएमओ ने रोगी कल्याण समिति के पास उपलब्ध राशि की भी जानकारी दी। कलेक्टर श्री कुमार ने सीएमएचओ डॉ डीएस चौहान को निर्देश दिए कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों में कैसे बेहतर कार्य कर सकते है। इस पर ज्यादा फोकस करते हुए व्यवस्थाएं जुटाने के निर्देश के दिए। इस दौरान एसडीएम बीएस कलेश, नपा उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल, पार्षद श्रीमती रजनी भंडारी उपस्थित रहें।

वेंडर चार दिवसीय हड़ताल पर उतरे, दिया ज्ञापन, सर्वर में आ रही तकनिकी परेशानियां

माही की गूंज, झाबुआ।

सर्वर में आ रही तकनिकी परेशानियों की वजह से उप पंजीयक कार्यालय झाबुआ, थान्दला, पेटलावद, मेघनगर जिला झाबुआ के सभी सेवा प्रदाता 05 जनवरी 2023 से 08 जनवरी 2023 तक हडताल पर जाने का निर्णय लिया है। इस सबंध में महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश भोपाल के नाम ज्ञापन सोपकर अपनी परेशानियों से अवगत कराते हुए चार दिवसीय हड़ताल पर उतर गए। ज्ञापन में बताया कि, उप पंजीयन कार्यालय झाबुआ, थान्दला, पेटलावद, मेघनगर जिला झाबुआ के सभी सेवाप्रदाताओं को सर्वर में आ रही तकनिकी खराबी के कारण कार्य में परेशानियों आ रही हैं, जिसके लिए झाबुआ जिले के सभी सेवा प्रदाताओ ने 05 जनवरी 2023 से 08 जनवरी 2023 तक हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। बैठक में उपस्थित सेवा प्रदाताओ ने बताया कि, सर्वर की खराबी के कारण बहुत परेशान हो गये है, लिमीट नही बन पा रही है। डीड कन्ज्युम करने के बाद गायब हो जाती है, स्टाम्प प्रिन्ट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। जिससे सेवा प्रदाताओं का अपने पक्षकार को जवाब देना मुश्किल होकर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। उपरोक्त परेशानियों के चलते सभी सेवा प्रदाता चार दिन हडताल पर रहेगे तथा इसके पश्चात भी सर्वर मे सुधार नही होने तथा परेशानिया यथावत रहने की स्थिति मे आगे भी हडताल जारी रहेगी तथा सभी सेवाप्रदाता कार्य नही करेगे। सेवाप्रदाता कार्य नही होने के कारण लोगो को रजिस्ट्री के लिए परेशान होना पड़ेगा। ज्ञात है कि, आनलाइन रजिस्ट्री शुरू होने के बाद से लोग लगातार परेशान हो रहे है, वही समय और पैसा भी ऑनलाइन रजिस्ट्री और स्टाम्प के लिये अधिक व्यय करना पड़ रहा है।

मानव कल्याण हेतु किया अपने नेत्रों का दान

माही की गूंज, बड़वानी।

बड़वानी निवासी सुरेशचंद्र मण्डलोई कुंडी वालो का निधन हो गया। उनकी इच्छा थी कि मरणोपरांत मानव कल्याण हेतु उनकी आंखे दान की जाए। इस पर उनकी इच्छानुसार उनके भतीजे श्री दिनेश मण्डलोई एवं श्री अरविंद मण्डलोई ने लायंस क्लब बड़वानी सिटी के अध्यक्ष लायन अनिल जोशी को अवगत करवाया। उन्होंने लायंस क्लब के नेत्रदान संयोजक लायन राम जाट से संपर्क किया। श्री जाट एवं डॉ ललित मालव नेत्र चिकित्सक द्वारा परिजनों से नेत्रदान सहमति पत्र भरवाकर नेत्रदान प्रक्रिया को संपन्न करवाया एवं कार्निया को सॉल्यूशन में प्रिजर्व करके आई बैंक की डायरेक्टर उमा झंवर से बात कर उन्हे इंदौर के एमके इंटरनेशनल आई बैंक भिजवाया। जहां से वह कार्निया जांच के बाद जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रत्यारोपित किया जाएगा। इस मानव सेवा कार्य में लायंस क्लब बड़वानी सिटी, सरस्वती नेत्र चिकित्सालय बड़वानी एवं परिजनों का सराहनीय सहयोग रहा।

लायन राम जाट ने बताया कि, भारत में कई लोग अंग प्रत्यारोपण के लिए भटक रहे है। जागरूकता की कमी के कारण अंगदान नहीं हो पाते है। ऐसे में मंडलोई परिवार द्वारा जागरूकता का परिचय देते हुए सुरेशचंद्र मंडलोई के नेत्रदान करवाए जो मरणोपरांत किसी और की जिंदगी को रोशन करेंगे।

कलेक्टर ने माण्डू उत्सव के लिए की जा रही तैयारियों का लिया जायजा

माही की गूंज, धार।

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आगामी सात जनवरी से आरम्भ होने वाले माण्डू उत्सव के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जामी मस्जिद परिसर में निर्माणाधीन मंच, फूड कोर्ट, पार्किंग स्थल, बैठक व्यवस्था, टेंट सिटी की तैयारियों का अवलोकन किया।

इस मौके पर इवेंट कम्पनी ई फेक्टर के राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मांडू महोत्सव का पांच दिवसीय आयोजन 7 से 11 जनवरी तक होगा। उन्होंने बताया कि पिछले सालों से मांडू महोत्सव की लोकप्रियता बढ़ी है। साल की शुरुआत में मांडू महोत्सव प्रदेश के लिए एक अनूठा अवसर है। प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी को इंदौर में आयोजित होगा। इस दौरान दुनिया भर से आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए मांडू के वैभव का प्रदर्शन प्रदेश के लिए गर्व की बात है। यह महोत्सव विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से जीवन के उत्सव को सामने लाता है। जिसमें कुछ बेहतरीन संरक्षित स्थापत्य स्मारकों और गेस्ट्रोनोमी प्रसन्नताओं की यात्रा भी शामिल है। घरेलू पर्यटकों के अलावा, हम प्रवासी भारतीय दिवस से मांडू आने वाले विदेशी यात्रियों के एक बड़े दल की उम्मीद कर रहे है। पुरानी दुनिया के आकर्षण को प्रतिध्वनित करने वाला एक जीवत शहर, मांडू अपनी विरासत, संस्कृति, वास्तुकला और जीवाश्म इतिहास के लिए जाना जाता है। यहां क्यूरेटेड ऐतिहासिक सैर, अनुभवात्मक साइकिल यात्रा, नृत्य की पारंपरिक लोककला कलाए, सुबह का योग, पाक प्रसन्नता, कला और शिल्प, संगीतमय सोरी और बहुत कुछ होगा। गर्म हवा के गुब्बाव्वारों से हवाई दृश्य शहर के किलों और खंडहरों की खोज करने के लिए एक शानदार अनुभव प्रदान करेगा। जबकि रेवा कुंड में शाम की मां नर्मदा आरती उत्सव की रौनक बढ़ा देगी। महोत्सव के दौरान कोई भी ग्रामीण पर्यटन भ्रमण में भाग ले सकता है । जिसमें स्थानीय कला, व्यंजन और संस्कृति का पता लगाने के लिए आस-पास के स्थानों की यात्रा शामिल है। मांडू महोत्सव के पांच दिनों के एक्शन पैक में सभी के लिए कुछ न कुछ है। मांडू महोत्सव सुबह के योग मांडू साइकिलिंग टूर और फूड एंड आर्ट एंड क्राफ्ट डिस्ट्रिक्ट को फिर से जीवत करने जैसी गतिविधियों के साथ घरेलू और अंतराष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को आकर्षित करेगा। मांडू हेरिटेज वॉक और इंस्टाग्राम टूर, उत्सव के हिस्से के रूप में, शहर के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ग्रामीण पर्यटन पर्यटन शहर के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करेगा और स्मारकों की यात्रा बीते युग के लिए भावनाओं को जगाने के लिए बाध्य है। मध्यप्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयास में राज्य सरकार और मप्र पर्यटन बोर्ड ने राज्य की सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों की है। इंदौर के करीब स्थित मांडू की अनूठी संस्कृति और विरासत है। यह क्षेत्र झीलों, किलों और स्वदेशी जनजातियों का दावा करता है।

ज्ञात हो कि, मध्य भारत के पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडू अपने झरनों, झीलों और अविश्वसनीय स्मारको के शानदार दृश्यों से पर्यटकों को आकर्षित करता है। मांडू बाज बहादुर द्वारा अपनी रानी रूपमती की याद में बनवाए गए महल के लिए पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है। लगभग भारत के केंद्र में स्थित मांडू ने देश के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मांडू की यात्रा के लिए मानसून का मौसम सबसे अच्छा समय है क्योंकि झीले और तालाब पानी से भरे हुए हैं और काले बादल ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी परिदृश्य के बीच एक सुखद वातावरण बनाते हैं। मांडू में अफ्रीकी मूल के बाओबाब पेड़ और अविश्वसनीय अफगान वास्तुकला महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है। इस क्षेत्र की कुछ संरचनाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित किया गया है, जिसमें रूपमती का मंडप भी शामिल है जो मांडू के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है।

गौ पालकों की लापरवाही के कारण प्लास्टिक कचरा खाने को मजबूर गोवंश

जब तक दूध दिया तब तक खुटे पर फिर छोड़ दिया आवारा

माही की गूंज, आम्बुआ।

आम्बुआ ही नहीं अपितु आसपास के ग्रामीण तथा शहरी कस्बाई क्षेत्रों में गोवंश दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। पशुपालक इन्हें तब तक खुटे से बांधते हैं जब तक गाय दूध देती है। उसके बाद बच्चे सहित आवारा छोड़ दिए जाते हैं जो कि बाजारों में कचरा खाकर अपना पेट भरते हैं तथा कई निर्दयी लोग की लाठी पत्थर खाते हैं।

गाय को माता माना गया है, मगर क्षेत्र में इसी माता को आवारा छोड़ दिया जा रहा है। आम्बुआ में 2 दर्जन से अधिक गोवंश आवारा होकर बाजारों में भटकते देखे जा सकते हैं। यह दुकान के सामान या सब्जी विक्रेताओं की सब्जी तथा रात में खेतों में खड़ी फसल को जब खाते हैं तो इन्हें डंडे से मारा पीटा जाता है। कई कसाई जैसा व्यवहार करते हुए अकारण ही इन घूमते गोवंशों पर लढ़ चला देते हैं अथवा पत्थर मार देते हैं, जिससे कई बार यह घायल हो जाते हैं। आवारा घूमते हुए जब कहीं इन गायों का प्रसव हो जाता है तो पता लगते ही गौपालक इन्हें घर ले जाकर खूंटे से बांध देते हैं तथा जब तक दूध देती है तब तक बांधकर खिलाया पिलाया जाता है। इसके बाद बच्चे सहित भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। कई बार यह जानवर किन्हीं वाहनों की चपेट में आकर घायल या फिर दम तोड़ देते हैं। क्षेत्र में 12 माह आवारा गोवंश भटकते रहते हैं। धर्म प्रेमी परिवार इन्हें रोटियां देते हैं। भूखे-प्यासे यह गोवंश बाजारों में पड़ा कचरा, प्लास्टिक आदि खा कर पेट भरते हैं। आम्बुआ में वर्षों से कांजी हाउस की व्यवस्था नहीं है तथा आसपास कोई ऐसी गौशाला भी नहीं है जहां इन्हें रखा जा सके। मजबूरन इन्हें सर्दी, गर्मी तथा बरसात में जहां-तहां रात गुजारना पड़ता है। प्रशासन को चाहिए कि, पशुपालकों का पता लगाकर या चिन्हित कर कडाई के साथ अपने गोवंश की कथा सुरक्षा तथा भरण पोषण कराऐ।

जंगल में तेंदुए का शव मिला, तेंदुओं के बीच हुई लड़ाई में एक की जान जाने का अंदेशा

माही की गूंज, अलीराजपुर।

जिले के ग्राम पंचायत रिंगोल के केलकुआ में एक तेंदुए का शव मिला है। तेंदुए की उम्र करीब दो वर्ष बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है, दो तेंदुओं की आवाज रात को आ रही थी। संभवतः दोनों के बीच लड़ाई हुई और एक की मौत हो गई। हलांकि तेंदुए के शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं है। तेंदुए का शव, किसान विक्रम पिता गोकुल के मकान के पास मिला। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे। अलीराजपुर एसडीओ एसएस ओहरिया व आजाद नगर रेंजर संदीप रावत अमले के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों का कहना है, अभी मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का स्पष्ट कारण पता चलेगा। तेंदुए के शव को पीएम के लिए आलीराजपुर ले जाया गया है।

ड्राइवर को आ गई झपकी, महिला समेत 3 लोगों की मौत

गुना।

जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र के रानी खेजड़ा गांव के पास एनएच46 हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। जिसमें महिला समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ड्राइवर को झपकी आने के कारण यह कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई है जिस कारण यह हादसा हुआ है। सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने मृतकों की तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। स्विफ्ट कार धार जिले से देपालपुर से बरेली जा रही थी। लेकिन चाचौड़ा थाना क्षेत्र के रानी खेजड़ा गांव के पास स्विफ्ट कार के ड्राइवर की झपकी लग गई। झपकी लगने के कारण कार पूरी तरह अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। कार में बैठे दो व्यक्ति और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का शिकार गाड़ी का नंबर एमपी 09 सीजेड 4902 है। इस हादसे में मृतक दिनेश दास आश्रम बुजुर्ग जिला धार का रहने वाला है तो वहीं दूसरा मृतक चालक सचिन देपालपुर का रहने वाला है और तीसरी मृतक महिला नीलम आगरा की रहने वाली है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच गई और सभी मृतकों के शव चाचौड़ा पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं।

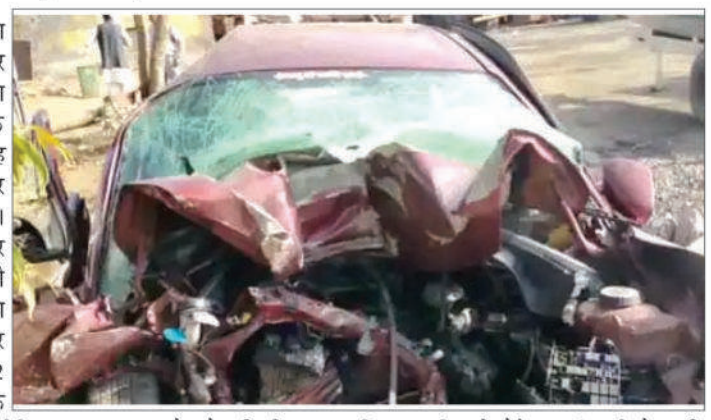

रेन बसेरा सस्ती सुलभ यात्री धर्मशाला के अभाव में महाकाल लोक अप्रासंगिक

माही की गूंज, उज्जैन।

अखिल भारतीय ब्राम्हण समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, महामंत्री पंडित तरुण उपाध्याय ने एक प्रेस वक्तव्य जारी कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि, 700 करोड़ रुपए तथा सेकंड फेस में और करोड़ों रुपए खर्च कर महाकाल लोक फेस वन, फेस टू के निर्माण कार्य कराए गए हैं और प्रस्तावित भी हैं। किंतु यात्रियों की दर्शन हेतु आने की संख्या को देखते हुए समस्त उपरोक्त निर्माण कार्य इसलिए अप्रसांगिक है, क्योंकि महाकाल लोक का प्रोजेक्ट बनाने वाले अधिकारी गणों ने यात्रियों की सुविधा के लिए सोच के साथ कोई व्यावहारिक योजना नहीं बनाई। मल्टी लेवल पार्किंग के लिए महाकाल के आसपास जमीनों का अधिग्रहण किया गया, किंतु साधारण पार्किंग बनाया गया जो मात्र 125 चौपाया वाहन की संख्या की पार्किंग क्षमता नहीं रखता। जिसके कारण महाकाल के संपूर्ण आसपास के क्षेत्र में आए दिन जाम लग रहा है। जिससे रहवासी क्षेत्र की आम जनता भी परेशान हो रही है। साथ ही दर्शनार्थियों की महाकाल लोक दर्शन करने की बढ़ती हुई संख्या के कारण यात्री ठहरने के लिए धर्मशाला एवं होटलों का अभाव महसूस कर रहे हैं तथा मनमाना शुल्क देकर ठहरने रुकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इतनी बड़ी योजना में आवश्यकता इस बात की थी कि, महाकाल लोक के आसपास ऐसे परिसर में सस्ते और सुलभ यात्रियों को ठहरने के लिए सस्ती और कम दर पर रैन बसेरों का अथवा यात्री निवास ग्रह का निर्माण कराया जाना था ताकि यात्री सुविधाजनक तथा कम शुल्क में महाकाल के आसपास रुक कर विश्राम कर भगवान महाकाल व अन्य तीर्थ स्थलों के दर्शन कम शुल्क में कर सके।

ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह मांग की है कि, महाकाल अथवा आसपास के क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधा हेतु बड़े रेन बसेरा अथवा यात्रि ग्रहों का निर्माण की योजना को तुरंत महाकाल लोक में प्रस्तावित कर प्राथमिकता के साथ पहले ऐसे निर्माण को कराया जाए। ताकि यात्रियों को सुविधा एवं कम शुल्क में गरीब यात्रियों के लिए भी भगवान महाकाल एवं उज्जैन नगरी के सुलभ दर्शन हो सके।

मछुआरों को दिया प्रशिक्षण

माही की गूंज, खरगोन।

मत्स्य विभाग के सहायक संचालक रमेश मौर्य द्वारा बुधवार को विभागीय मछुआ प्रशिक्षण योजना अंतर्गत करही के चिंनगुन में विकास मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित के मछुआरों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में संस्था चिंनगून के 50 मछुआरों को विभाग से संबंधित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, झींगा पालन, मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्यबीज उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, जाल बुनने आदि योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में नगर परिषद करही अध्यक्ष नंदकिशोर खेडेकर, उपाध्यक्ष महेश आसवानी एवं विशेष अतिथि मत्स्य समिति अध्यक्ष दीपक, मत्स्य निरीक्षक खरगोन के जतन रावत द्वारा हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया।

ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष ने किया क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन

माही की गूंज, बरझर।

स्वतंत्रा सेनानी प्रथी दादा एवं स्व. कलावती भूरिया की स्मृति में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन बरझर के टंकी मैदान में आयोजित किया जा रहा है। जिसका प्रथम पुरस्कार 21 हजार रुपए व द्वितीय पुरस्कार 11 हजार रुपए रखा गया है। पुरस्कार राशि पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल द्वारा विजेता व उपविजेता टीम को दिया जाएगा। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन आजाद नगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लाइक मोहम्मद सेख, हरीश भाई, लक्ष्मी नारायण राठौर, विक्रम साहू, इरशाद खान, महेश मावी, सोमला बारिया, प्रथी भाई आयोजक समिति के शाहरुख खान, एजाज खान, आदिल बेग, अरसद गोलु, साज़िद खान व क्रिकेट प्रेमियों की मौजूदगी में नारियल श्रीफल छोड़कर क्रिकेट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच आंबुआ व बरझर के बीच खेला गया। टूर्नामेंट में भाबरा, कटठिवाडा व आसपास क्षेत्र की टीम भाग ले रही है। वही उक्त टूर्नामेंट का फाइनल मैच 7 जनवरी को खेला जाएगा।

कलेक्टर ने की जिले में जारी निर्माण मरम्मत कार्यों की समीक्षा की

धार।

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कलेक्ट्रेट सभागार में ज़िले में जारी निर्माण मरम्मत कार्यों की समीक्षा की। जिला पंचायत सीईओ केएल मीणा सहित सम्बन्धित अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन कार्य की प्रगति व गुणवत्ता परखने के लिए ग्राम सभा तदर्थ समितियों का गठन करें। साथ ही इस सप्ताह लंबित भुगतान करें। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले उप व सहायक यंत्रियों को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि अतिक्रमण हटाकर कार्यो को आरंभ करें। कन्या विद्यालय धार में प्लास्टर तथा अन्य कार्यों को शीघ्र पूर्ण करें। कार्यों की गुणवत्ता अलग एजेंसी से क्रॉस चेक कराएं। छात्रवासों में किए गए कायाकल्प का अभिलेख संधारित करें। विद्यार्थियों के फीडबैक विडियो सोशल मीडिया पर साझा करें। साथ ही आगामी सप्ताह में ठेकेदारों की मीटिंग करें, प्रगति बताएं। हॉस्टल में बोर्ड लगाकर किए गए कार्यों को प्रदर्शित करें। स्मॉर्ट क्लास निर्धारित समयावधि में आरंभ हो।

निलंबित भाजपा नेता का होटल धाराशाई, कार से युवक को कुचलने का आरोप

सागर।

पुलिस-प्रशासन ने भाजपा से निलंबित किए गए एक नेता पर बड़ी कार्रवाई की है। एक हत्या के आरोपी निलंबित भाजपा नेता मिश्री चंद गुप्ता का होटल प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि, सागर जिले में बना यह होटल अवैध था। मिश्री चंद गुप्ता पर आरोप है कि, 22 दिसंबर को उन्होंने जगदीश यादव नाम के एक शख्स को एसयूवी कार से रौंद दिया था।

निलंबित भाजपा नेता के होटल को ढहाए जाने का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि किस तरह चंद मिनटों के अंदर यह होटल धाराशाई हो गया। सागर जिले के कलेक्टर दीपक आर्य, डीआईजी तरूण नायक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी होटल को गिराए जाने के वक्त वहां मौजूद थे।

मिश्री चंद गुप्ता का यह होटल सागर जिले में माकारोनिया इंटरसेक्शन के नजदीक स्थित था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए होटल को गिराते वक्त वहां यातायात को रोक दिया गया था। इसके अलावा चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई थी। होटल के आसपास रह रहे लोगों को भी पहले ही अलर्ट किया गया था। जिलाधिकारी ने बताया कि बिल्डिंग को गिराने जाने से अन्य चीजों को किसी तरह क्षति नहीं पहुंची है।

कोरेगांव के रहने वाले जगदीश यादव की एसयूवी से कुचल कर हत्या की गई थी। इस हत्या का आरोप भाजपा नेता मिश्री चंद गुप्ता और उनके परिवार के सदस्यों पर लगा था। इस मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। इनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि निलंबित भाजपा नेता अभी भी फरार है। जगदीश यादव निर्दलीय पार्षद किरण यादव के पति थे। एमपी निकाय चुनाव में किरण यादव ने मिश्री चंद गुप्ता की पत्नी मीना को 83 वोटों से हराया था। जगदीश यादव की मौत को लेकर यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि उनकी हत्या चुनावी रंजिश में की गई है।

सफेद सोने के भाव गिरे, व्यापारियों को लाखों का घाटा, कृषक भी चिंतित

माही की गूंज, आम्बुआ।

खेतों में रात-दिन खून पसीना बहा कर तथा खाद बीज पर खर्चा करने के बाद कृषकों को अच्छी उपज तथा बाजार में अच्छा भाव मिलने की उम्मीद रहती है। वैसे भी किसनी को मानसून का जुआ कहा जाता है। यदि मौसम का साथ मिला तो फसलों की बंपर पैदावार होती है और मौसम बिगड़ा तो फसलें चौपट होना ही है। इन सबसे जूझता किसान जब फसल लेकर बाजार में आए और भावना ही न मिले, तब क्या हालत होती होगी या फिर से जब प्रथम बार बाजार में आए और भाव अधिक मिले मगर व्यापारियों के गोदाम में आते ही गिर जाए तब व्यापारियों की हालत क्या होती होगी, यह वर्तमान में सफेद सोना कहे जाने वाले कपास ने दिखा दिया।

इस बार क्षेत्र में कपास की प्रथम आवक जोरदार रही और भाव भी जोरदार निकले। कपास के थोक भाव 8-10 दिन पूर्व 80 से 90 रूपये प्रति किलो यानी 8 से 9 हजार प्रति कुंटल खरीदी व्यापारियों ने की तथा कई व्यापारियों ने तत्काल माल बाहर भी भेज दिया। इस प्रथम फसल आवक में अच्छे भाव मिलने से कृषकों में खुशी छा गई। मगर एक हफ्ते बाद ही भाव 60-70 रूपए किलो यानी कि 6 से 7 हजार रुपए क्विंटल हो गए जिस कारण कृषक चिंतित हो रहे हैं। स्मरण रहे कि, कपास की फसल एक साथ नहीं आती है जैसे-जैसे फूल खिलते हैं कृषक उन्हें एकत्र करते हैं। इस फसल में पानी, दवाई आदि के साथ-साथ मौसम की अनुकूलता भी उत्पादन को प्रभावित करती है। उचे भाव में जिन व्यापारियों ने माल खरीद कर गोदामों में स्टॉक किया और जब कि बाजार (मंडी) में भाव गिरे तो कई व्यापारियों को लाखों का चूना लग गया। जिसके चलते कई बड़े व्यापारी सकते में दिखाई दे रहे हैं। इधर कृषक एक हफ्ते पूर्व मिले भाव पर कपास बेचना चाहते हैं मगर कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। जो खरीद रहे हैं 60-65 तथा अच्छा माल होने पर 68-70 रूपए किलो खरीद रहे हैं। इन खरीदी पर भी व्यापारी आशंकित है कि भविष्य में कहीं और भाव गिरे तब क्या होगा। स्थिति यह है कि अभी व्यापारी कृषक दोनों ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं।

नए साल के साथ कांग्रेस में पोस्टरवार शुरू, रात में लगे पोस्टर को देखकर विधायक की खुली नींद

पत्रकारों के घर टिफिन भेजकर नए वर्ष में किरकिरी करवाने वाले विधायक साहब अब आर्थिक सहायता की राशि का लगाएंगे मरहम

माही की गूंज, पेटलावद।

मालू डामोर के लगे पोस्टर के पास ही लगाए गए पोस्टर, कांग्रेस के नए स्लोगन के साथ बधाई।

31 दिसम्बर की रात में लगे जिला पंचायत उपाध्यक्ष के फ्लेक्स।

दिन में विधायक मेडा के पोस्टर लगाने की तैयारी शुरू।

और से दावेदारी के लिए ज्यादा विकल्प नही है, लेकिन जयस संगठन की इंट्री के बाद दोनों मुख्य दलों को अपनी योजना में परिवर्तन करना पड़ रहा है और नए चेहरे की और देख रहे हैं, ताकि जयस संगठन की काट कर सके। कांग्रेस का रुख कही न कही जयस संगठन की और दिखाई देता है, जिसके चलते कांग्रेस में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और वो अब देखने को भी मिल रहा है। नगर में मुख्य स्थानों पर लगे पोस्टर इसका प्रमाण दे रहे हैं। विगत चार साल से अपने घोड़ो को अस्तबल में खड़े रखने वाले क्षेत्र के विधायक वालसिह मेडा अब मैदानी घोड़े दौड़ा रहे है, ताकि 2023 के चुनाव में सक्रिय दिखकर कांग्रेस का टिकिट प्राप्त कर सके। दूसरी ओर इस बार विधायक वालसिंह मैडा को टिकिट के लिए मुश्किल चुनौती मिलना तय है।

पोस्टर से शुरू 2023 का सफर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लगे पोस्टर तो विधायक की खुली नींद

इस प्रकार से भोजन के पेकेट भेजे गए पत्रकारों के घर।

नये वर्ष में कांग्रेस पार्टी ÷नया साल, नई सरकार÷ के संकल्प के साथ जनता के बीच पहुचने का निर्णय लिया। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि, नये वर्ष की शुरुआत के अवसर पर पूरे प्रदेश में इस अभियान के होर्डिंग भी लगाये जायेंगे। क्षेत्र के नेताओ को लोकसभा, विधानसभा एवं ब्लॉक स्तर पर लगने वाले होर्डिंग के स्वीकृत डिज़ाइन भेजे गए।

क्षेत्र में होर्डिंग लगते ही उसके फ़ोटो हमें व्हाट्सअप पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि उसे सोशल मीडिया पर प्रचारित करने के साथ-साथ वरिष्ठ नेताओं तक ÷नया साल, नई सरकार÷ अभियान के प्रचार-प्रसार की रिपोर्ट भी भेजी जा सके। ये कांग्रेस के लिए एक टास्क के समान था जिसकी जानकारी शायद विधायक वालसिंह मैडा तक देर से पहुची। 31 दिसम्बर की रात को पेटलावद के मुख्य मार्गो पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष अकमाल मालू डामोर ने नया साल नई सरकार स्लोगन के साथ पोस्टर लगाकर कांग्रेस की टिकिट पर पेटलावद विधानसभा में मैदान में उतरने के मंसूबे साफ कर दिए। पोस्टर लगते ही मामला सोशल साइड के जरिये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पेज पर पहुच गया। जिसकी जानकारी कांग्रेस विधायक तक पहुची, तब विधायक साहब भी सक्रिय हुए और ताबड़तोड़ फ्लेक्स बना कर अगले ही दिन नगर के मुख्य मार्गो पर जहा पहले से अलमाल डामोर के पोस्टर लगे थे उसके पास लगा दिए गये। पोस्टरवार के साथ अब कांग्रेस में पेटलावद विधानसभा में टिकिट के लिए दावा करने का दौर शुरु हो गया हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष की इंट्री नें विधायक वालसिह मैडा की परेशानियां बढ़ा दी है और यहा उनकी सक्रियता नजर भी आने लगा है।

पत्रकारों के घर भेज दिए भोजन के पैकेट, घिरे तो खेद व्यक्त कर अब आर्थिक सहायता का मरहम लगाने का प्रयास

नए साल की शुरुआत विधायक मैडा के लिए कुछ ठीक नही रही। एक ओर रात में लगे पोस्टर ने चिंता बड़ा दी, तो दूसरी ओर विधायक साहब के गुर्गे नए साल में नगर के पत्रकारों के घर प्लास्टिक की थैली में पैक भोजन का पैकेट पहुचा दिये। जिससे पत्रकार नाराज़ होकर विधायक साहब के इस कार्य का विरोध करने लगे, कही न कही पत्रकारो के मान सम्मान की ठेस पहुचाने का काम विधायक की ओर से किया गया। पत्रकारो की नाराजगी की जानकारी जैसे से विधायक साहब को लगी, विधायक साहब ने सभी पत्रकारों को उनके निवास पर अगले ही दिन बुलाकर भोजन पेकेड वाली व्यवस्था पर सफाई दी और गलती स्वीकार की। बताया जा रहा है चुनावी साल को देखते हुए विधायक साहब सरकारी राशि से खुद का और पत्रकारों के भले की सोच रहे हैं और आर्थिक सहायता की राशि से पत्रकारों को खुश करने की सोच रहे हैं।

ये चुनाव अलग होगा

हर बार की तरह पेटलावद विधानसभा को रटे-रटाये प्रत्याशी मिलना इस बार मुश्किल है। इस बार चुनाव अलग है और नए-नए चेहरे जनता को मिल सकते है। वही पुराने चेहरों से ऊब चुकी जनता भी क्षेत्र के लिए नए चेहरे की और देख रही है। देखना ये दिलचस्प होगा कि, जनता की मनोदशा को कोंनसा दल भाप कर टिकिट तय करेगा। जयस संगठन की उपस्थित ने युवा ओर नए चेहरे पर मोहर लगा दी है, जो पिछले पंचायत चुनाव में देखने को मिल चुका है जहा नए ओर युवा चेहरे बड़ी संख्या में जीत कर आये हैं।

इंडियन नेशनल कांग्रेस के पेज पर किया गया शेयर, मालू डामोर का पोस्टर।

प्रशासन आए अपनी कारस्तानियों से बाज, अपनी मनमानी व नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए पत्रकारों को न बनाएं मोहरा

शिकायतकर्ता के दबाव के चलते सेल्समेन कह रहा कर लूंगा आत्महत्या, पत्रकार का नाम गलत लिखा है जांच के बाद खंडन किया जाएगा- सयुक्त कलेक्टर

माही की गूंज झाबुआ।

राशन वितरण व्यवस्था में हो रही लापरवाही को लेकर जिले में कई बार सवाल उठे हैं। हाल ही में राशन वितरण में मनमानी के चलते कलेक्टर के निवास व कार्यालय के साथ सड़कों पर प्रदर्शन भी किया गया है। तय है उक्त प्रदर्शन को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि, राशन वितरण व्यवस्था में किस तरह से लापरवाही की जा रही है और पात्र व्यक्तियों को मिलने वाला राशन बाजारों में बेच सेल्समैन से लेकर अधिकारियों ने अपने व्यारे-न्यारे कर लिए हैं। वही चुनावी वर्ष के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान भी राशन वितरण व्यवस्था में सख्त नजर दिखाई दे रहे है।

बावजुद राशन वितरण व्यवस्था में लापरवाही के मद्देनजर झाबुआ में तीन बार हुए प्रदर्शन का मामला शांत हुआ ही नहीं था कि, मेघनगर ब्लाक की ग्राम पंचायत बेडावली से मेघनगर व रम्भापुर पत्रकारों को कुछ ग्रामीणों द्वारा शिकायत की जाती है कि, उन्हें 1 माह से अधिक समय हो जाने के बाद भी खाद्यान्न नहीं दिया गया व किसी को खाद्यान्न दिया भी गया तो कई बार खाद्यान्न हेतु लाइन पर लगने व शाम होने के बाद दूसरे दिन व दूसरे दिन आने पर तीसरे दिन आने का कहकर परेशान कर खाद्यान्न दिया जाता है। वही स्थिति 27 दिसंबर को सेल्समेन द्वारा खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है आज भी इसी परेशानी का सामना कई पात्र व्यक्तियों को भुगतना पड़ेगा, कहते हुए ग्रामीणों ने मामला प्रकाशित करते हेतु पत्रकारों को शिकायत कर जानकारी दी।

ग्रामीणों की शिकायत पर रम्भापुर, मेघनगर के कुछ पत्रकार सामूहिक रूप से मामले का कवरेज करने बेडावली की शा.उ.मुल्य की खाद्यान्न वितरण दुकान पर पहुंचे ताकि पत्रकारों के कवरेज के साथ मामले को शासन-प्रशासन के सामने लाकर समस्या का समाधान हो सके। मौके पर पहुंचे पत्रकारों को 27 दिसंबर को खाद्यान्न वितरण के समय पात्र उपभोक्ताओं ने खाद्यान्न वितरण में सेल्समैन द्वारा की जा रही कुछ लापरवाहीया बताई। जिसमें एक महिला ने पत्रकारो को कैमरे के सामने बताया, सेल्समैन द्वारा 3 माह तक अंगूठे लगवाए परंतु आज आना, कल आना कहकर परेशान करता है और आखिर में धान खत्म हो गया है कह देता है। पर मुझे पिछले 3 माह से खाद्यान्न नहीं दिया। वहीं अन्य पात्र उपभोक्ताओं ने भी अपनी समस्या बताकर खाद्यान्न वितरण में मनमानी की बात बताई।

वही कलेक्टर रजनी सिंह 28 दिसंबर को मेघनगर-रम्भापुर क्षेत्र के दौरे पर होने के चलते बेडावली गए पत्रकारों से रूबरू हुई और पत्रकारों ने ग्रामीणों द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितताएं होने के संबंध में पत्रकारों के समक्ष की गई शिकायत से कलेक्टर को अवगत करवाया। जिस पर कलेक्टर ने भी ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत की जानकारी पत्रकारों के माध्यम से मिलने पर मामले की जांच करवाई जाएगी और शिकायत सही पाई गई तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया।

जिसके बाद 27 व 28 दिसंबर को एक से अधिक न्यूज़ चैनल, यू-ट्यूब चैनल के साथ समाचार पत्र में भी खाद्यान्न वितरण को लेकर शिकायतकर्ताओं की शिकायत के साथ कलेक्टर के दिए आश्वासन के साथ समाचार प्रकाशित किए थे। समाचार प्रकाशित होने के बाद संबंधित विभाग और जिला प्रशासन को चाहिए था कि, मामले में उपभोक्ता जिन्होंने शिकायत की है से रूबरू होकर खाद्यान्न वितरण में कहा अनियमितताएं हो रही की जांच कर सामने आई उक्त समस्या का समाधान किया जाना चाहिए था। अगर शिकायतकर्ता गलत है और खाद्यान्न वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही थी तो शिकायतकर्ता पर पत्रकार एवं प्रशासन को गुमराह करने के संबंध में कार्रवाई की जाना चाहिए थी। अगर शिकायत सही है तो संबंधित कर्मचारी व अधिकारी पर कार्रवाई करने की आवश्यकता थी।

आपूर्ति अधिकारी धर्मेंद्रसिंह ने अपनी कारस्तानी को छुपाने के लिए प्रशासन को किया दागदार

उपरोक्त शिकायत व जांच, जांच के बाद जो भी खुलासा प्रशासन करती उसका संकलन भी पत्रकार करते लेकिन ऐसा कुछ भी ना होकर रूटिंग कार्रवाई को, पत्रकार दशरथ कड्डा द्वारा गलत एवं शिकायती समाचार चलाने की धमकी दी गई और गलत समाचार व वीडियो प्रसारित करने का जिला जनसंपर्क कार्यालय में मीडिया प्रेस नोट जारी किया। जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और सामने आया की उक्त घिनौना कृत्य खाद्य एवं आपूर्ति कनिष्ठ अधिकारी धर्मेंद्रसिंह ने अपनी अनियमित्ताओं को छुपाने एवं कार्रवाई से बचने के लिए पत्रकार को मोहरा बनाकर प्रेस नोट जनसंपर्क कार्यालय को हथियार बनाकर पत्रकार एवं पत्रकारिता की छवि को खराब करने तथा राशन वितरण में कहीं भी लापरवाही हो तो पत्रकार समाचार का संकलन करने में दस बार विचार करेगा की बद्दिनयती के साथ यह घिनौना कृत्य किए जाने का मामला सामने आया। इस संबंध में जब कनिष्ठ आपुर्ति अधिकारी धर्मेन्द्रसिंह से गूंज ने बात की तो जो भी था वह कलेक्टर को सोप दिया है। कहकर बिना कुछ बताये ही अपनी ही कारस्तानी से बोखलाये धर्मेन्द्रसिंह ने फोन काट दिया और फिर बाद में फोन ही अटेन्ट नही किया।

यह किया प्रेस नोट जारी

''कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा खाद्यान्न वितरण के संबंध में निरीक्षण'', ''उचित मूल्य की दुकानों पर पर्याप्त राशन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है- कलेक्टर'' के शीर्षक के साथ जिला जनसंपर्क कार्यालय ने 29 दिसंबर को कलेक्टर के निर्देशन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा खाद्यान्न वितरण के संबंध में निरीक्षण करने पर पाया गया कि, खाद्यान्न समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में वितरीत किया जा रहा है। पत्रकार दशरथ कड्डा द्वारा प्रचारित वीडियो, समाचार के माध्यम से यह प्रचारित किया गया है कि, शासकीय उचित मूल्य दुकान बेडावली में 3-4 माह से पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। 27 दिसंबर को एसडीएम व नायब तहसीलदार मेघनगर एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी धर्मेंद्रसिंह द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान बेडावली की जांच की गई थी। जिसमें दुकान खुली रखकर वितरण किया जा रहा था एवं हितग्राहियों से पूछताछ भी की गई। जिसमें किसी भी प्रकार से कोई शिकायत दर्ज नही करवाई गई। कुछ लोगो द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि, सरकार 2 महीने का राशन दे रही है किंतु विक्रेता एक माह का

ही दे रहा है। जबकि वास्तव में सरकार हर माह 2 योजना का खाद्यान्न वितरण करवा रही है। इसमें एनएफएसए के तहत 2 किलो गेंहू एवं 3 किलो चावल 1रू किलो की दर से पीएमजीकेएवाय योजना के तहत 3 किलो गेंहू एवं 2 किलो चावल मुफ्त में दिया जा रहा है। चुकी झाबुआ आदिवासी जिला है यहां चावल खाने में ज्यादा उपयोग में नहीं आता है तो हितग्राही द्वारा चावल के स्थान पर गेंहू की मांग की जाती है नही दिए जाने पर खाद्यान्न वितरण में अनियमिता की शिकायत की जाती है। दिनांक 27 दिसंबर को जॉच के समय विक्रेता द्वारा अवगत कराया गया था कि, पत्रकार दशरथ कड्डा द्वारा किसी नजदीकी व्यक्ति को लाकर उसके लिए केवल गेंहूं की माग की गई थी। जिसे देने से विक्रेता द्वारा मना किए जाने पर पत्रकार द्वारा गलत एवं शिकायती समाचार चलाने की धमकी दी गई थी। तद्उपरान्त पत्रकार द्वारा इसी संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी जिला झाबुआ को फोन लगाकर शिकायत की गई एवं जिसकी जॉच हेतु सूचना विभाग द्वारा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के समक्ष भेजा गया और इसकी सूचना कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एव नायब तहसीलदार को दी गई। आज दिनांक को बेडावली संरपंच पति सुभाष से पूछे जाने पर बताया गया कि, राषन वितरण किया जा रहा है एवं पत्रकार द्वारा द्वेषपूर्ण एवं गलत मंशा से समाचार प्रसारित किया गया है। पत्रकार दशरथ कड्डा के विरूद्ध उचित अनुशासत्मक कार्यवाही हेतु विक्रेता द्वारा आवेदन क्रमांक 162/1962 प्रस्तुत किया गया है।

गूंज पड़ताल: जनसंपर्क कार्यालय से जारी प्रेस नोट में बताई कार्रवाई की जांच करें कलेक्टर

जिला जनसंपर्क कार्यालय से जारी प्रेस नोट में पत्रकार पर झूठे आरोप मढ़ने एवं जनसंपर्क सें जारी समाचार में कई विसंगतियां सामने आने पर गूंज ने पड़ताल की तो, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की अपनी मनमानी सामने आकर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी धर्मेंद्रसिंह की कारस्तानी संदेह के घेरे में सामने आया।

हकीकत यह

कलसिंग मचार एवं ग्रामीणों ने खाद्यान्न वितरण में मनमानी किए जाने की शिकायत पर एक से अधिक पत्रकार समाचार के संकलन हेतु बेडावली शासकीय मूल्य की दुकान खुलने के बाद पहुंचे। जहा सेल्समैन गौरसिंह पारगी खाद्यान्न वितरण कर रहा था। कुछ ग्रामीणों ने मीडिया के कैमरों के सामने शिकायत की कि, किसी को अंगूठा लगाने के बाद भी 3 माह तक खाद्यान्न नहीं मिला और बाद में कह देते हैं खाद्यान्न खत्म हो गया, तो हमारा खाद्यान्न कहां गया...? वहीं यह भी ग्रामीणों ने बताया कि, 2-3 दिन तक लाइन में लगने के बाद भी खाद्यान्न नहीं दिया जाता है। उक्त शिकायत के बाद एक समाचार पत्र ने 27 दिसंबर का संकलन कर 28 दिसंबर को समाचार प्रकाशित किया वहीं क्षेत्र में 28 दिसंबर को कलेक्टर के दौरे के समय पत्रकारों ने बेडावली की खाद्यान्न वितरण समस्या को बताया, जिसपर कलेक्टर ने जांच करवा कर ग्रामीणों की शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। कलेक्टर के आश्वासन के साथ ही करीब 4 से 5 न्यूज़ चैनल एवं यूट्यूब चैनल पर समाचार प्रकाशित हुए और पत्रकार दशरथ कड्डा के न्यूज़ चैनल में भी 28 दिसंबर को कलेक्टर की बाइट के साथ समाचार प्रकाशित किया गया था। तो 27 तारीख को दशरथ कड्डा द्वारा प्रसारित समाचार जारी का उल्लेख प्रेस नोट में केसे किया गया...?

वही स्थानीय पत्रकारों को नायब तहसीलदार ने बताया कि, रूटिंग निरीक्षण के दौरान बेड़ावाली पहुंचे थे और वहां खाद्यान्न वितरण हो रहा था जो खाद्यान्न उपभोक्ता ले रहे थे उनसे समस्या जानी तो बताया खाद्यान्न मिल रहा है। निरीक्षण के दौरान न हीं ग्रामीणों की शिकायतों के बारे में पता था और न ही पत्रकारों द्वारा प्रकाशित किसी समाचार की जानकारी थी। उक्त बिंदु में पत्रकारों के आ जाने के बाद रूटिंग निरीक्षण में अधिकारी पहुंचे जिन्हें न ही ग्रामीणों की शिकायत व पत्रकारों के समाचार संकलन की जानकारी नहीं थी लेकिन खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने अपनी कारस्तानी को छुपाने के लिए पत्रकार के नाम के साथ मामले का रुख बदलकर अपने आप को बचाने के साथ प्रशासन को दागदार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह तय है कोई भी शासकीय दुकान पर खाद्यान्न वितरण करने वाला सेल्समैन बिना संबंधित अधिकारी की जानकारी व निर्देशों के बिना कुछ भी अनियमितताएं नहीं कर सकता है। चुकि कुछ भी अनियमित्ताए होती है तो उसके लिए सेल्समैन से ज्यादा खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी भी जवाबदार रहते है। यहां भी मामला उजागर होने के बाद धर्मेंद्रसिंह के बारे में दबी जुबान में बताया जा रहा है कि, यह क्षेत्र की सभी दुकानों के सेल्समैनो से प्रतिमाह एक फिक्स राशि लेते हैं।

आपूर्ति अधिकारी ने बनाया सेल्समैन व सरपंच पति को मोहरा

जब गूंज की पड़ताल में खाद्यान्न वितरण करने वाले सेल्समैन से बात हुई तो बताया आपूर्ति अधिकारी धर्मेंद्रसिंह के निर्देशानुसार ही दुकान पर खाद्यान्न वितरण करते हैं और साहब के निर्देशन में ही चावल की जगह गेहूं नहीं देते हैं। दशरथ कड्डा या कोई भी पत्रकार मेरे पास जो प्रेस नोट में जारी किया गया है उसके आधार पर किसी भी नजदीकी व्यक्ति को गेहूं दिलाने नहीं आए थे और ना ही मैंने किसी प्रकार का कोई लेटर पत्रकार के विरुद्ध किसी अधिकारी को नहीं दिया, मुझे मोहरा बनाया जा रहा है। सेल्समैन ने बताया कि, जो ग्रामीणों ने एसडीएम के नाम से पत्र लिखा वह मोबाइल पर भेजा जिसमें भी जो प्रेसनोट में बताया गया है ऐसा कुछ भी पत्रकार के विरुद्ध नहीं दर्शाया गया है। बता दे कि, 29 दिसंबर एसडीएम मेघनगर के नाम से ग्राम पंचायत बेडावली के लेटर पैड पर संस्था द्वारा संचालित शा.उ.मूल्य की दुकान के संबंध में प्रतिवेदन दिया। जिसमें सेल्समैन द्वारा नियमित व 90प्रतिषत खाद्यान्न वितरण होना बताया और शिकायतकर्ता की शिकायत को झूठा बताया गया।

सचिव किशोर कटारा से उक्त पत्र का जावक क्रमांक मांगा तो गुंज को बताया, ग्राम पंचायत की ओर से यह पत्र जारी नहीं किया गया है। वही पत्रकार दषरथ कड्डा ने बताया मैंने आपूर्ति अधिकारी से किसी प्रकार की कोई बात नही की लेकिन झुठा नाम लिया जा रहा है। अगर बात की होगी तो धर्मेन्द्रसिंह उसके काल डिटेल बता दे, मामले का कवरेज करने कई पत्रकार गये थे लेकिन मेरे नाम का प्रेस नोट में उल्लेख करने का कारण अधिकारी को बताना ही पडेगा। मामले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति प्रभारी एवं संयुक्त कलेक्टर श्री गर्ग से बात हुई तो गूंज को बताया, पत्रकार का नाम प्रेस नोट में जारी किया गया है जो व्यक्तिगत रूप से भी कहूंगा की गलत हे, मामले में पूरी जांच होने के बाद इसका खंडन प्रकाशित किया जाएगा। श्री गर्ग ने बताया कि, जानकारी मिल रही है की शिकायतकर्ता से परेशान होकर सेल्समैन आत्महत्या करने की बात कर रहा है और कह रहा है मेरी कोई गलती नहीं है फिर भी मुझे परेशान किया जा रहा है।

वही गूंज ने जानकारी निकाली तो सामने आया की सेल्समैन स्थानीय शिकायतकर्ता से ज्यादा आपूर्ति कनिष्ठ अधिकारी धर्मेंद्रसिंह से परेशान हो गया है। चुंकि किसी प्रकार का कोई पत्र लेखन या शिकायत पत्रकार के विरुद्ध नहीं करने के बाद भी अधिकारी ने बेमतलब से उसका नाम घसिटकर प्रेस नोट में जारी किया।

इस मामले में जिला जनसंपर्क अधिकारी सुधीर कुशवाह से बात कि तो बताया, उक्त प्रेस नोट खाद्य विभाग से जारी होकर आया था जिसे हम ने जारी किया। खाद्य विभाग ने क्या कार्रवाई की मुझे नहीं पता। खाद्य विभाग के माध्यम से जिला जनसंपर्क विभाग ने जारी किए प्रेस नोट में साफ दिखाई दे रहा है कि, प्रशासन अपनी मनमानी किस निचले स्तर तक जाकर करता है। वही पत्रकार का नाम इस तरह से जारी करने एवं उस पर कार्रवाई करने की बात के साथ जारी प्रेस नोट की हकीकत की जांच करवा कर कलेक्टर को तत्काल संबंधित गुनहगार अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए।

मामले में पत्रकार के विरुद्ध इस तरह से जारी किए गए प्रेस नोट पर जिला पत्रकार संघ अध्यक्ष राजेश सोनी के साथ सभी पत्रकारों ने प्रशासन के उक्त कृत्य की निंदा की है और कहा है इसकी निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करें नहीं तो पत्रकार संघ विरोध स्वरूप अगला कदम उठाएगा।

निरंतर....

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422